राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 48 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,19 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

तालिबान का विरोध शुरू : आतंकियों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई पत्रकार भी घायल

जलालाबाद में नागरिकों ने निकाली रैली

काबुल, (एजेंसी) । अफगानिस्तान में कुछ लोगों ने तालिबान की हुकूमत का विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने अफ्गानिस्तान का राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद यही झंडा हाथ में लेकर रैली निकाली। तालिबानियों ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी। स्थानीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान की फायरिंग में तीन लोगों की मौत हो गई है। कुछ पत्रकार व वीडियो जर्नलिस्ट्स भी घायल हो गए हैं।

अचानक फायरिंग

लोकल मीडिया ने इसके कुछ वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसमें लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे हैं। इसी दौरान इमारतों और सड़कों पर तैनात तालिबान ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान तालिबान के खिलाफ काफी नारेबाजी भी हुई।

पंजशीर में जमा हो रहीं तालिबान विरोधी फौजें

अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को अभी महज 4 दिन ही हुए हैं और इस हुकूमत के खिलाफबगावत शुरू हो गई है। तालिबान विरोधी फौजें पंजशीर में इकट्ठा हो रही है। इनमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर के सैनिक और अहमद मसूद की फौजें शामिल हैं। चारिकार इलाके में कब्जे के अलावा इन विद्रोही फौजों ने पंजशीर में नॉर्दन अलायंस, या यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट का झंडा भी फहरा दिया है। पंजशीर घाटी में 2001 के बाद पहली बार अलायंस का झंडा फहराया गया है।

देश छोड़ने के बाद गनी बोले

रुकता तो कत्लेआम हो जाता

अबू धाबी । तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर गए राष्ट्रपति अशरफगनी पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने यूएई से अफ्गानिस्तान की जनता को सम्बोधित किया है। इसमें अशरफ गनी ने कहा है कि अगर वह तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। आगे कहा गया है कि उनके पैसे लेकर अफ्गानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरह से अफ्वाह है। भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं हैए जो मुझे नहीं जानते वे फैसला ना सुनाएं।

यूएई ने दी शरण, देर रात बिगड़ी तबीयत

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफगनी इस वक्त यूएई में हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ही बयान जारी कर यह बात बताई थी। बयान में कहा गया कि यूएई ने मानवीय आधार पर राष्ट्रपति अशरफगनी और उनके परिवार का अपने देश में स्वागत किया है। वहीं ईरानी एजेंसी वाईजेसी ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी कथित तौर पर यहां के एक अस्पताल में भर्ती हैं।

पांच माह बाद सक्रिय मामले सबसे कम, केरल में हालात में नहीं हो रहा बदलाव

नई दिल्ली । केरल में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। पूरे देश में सामने आ रहे नए मामलों में से आधे से ज्यादा केरल में ही मिल रहे हैं। वैसे तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या पांच महीने में सबसे कम हुई है, परंतु नए मामले एक दिन पहले की तुलना में 10 हजार से ज्यादा बढ़ गए हैं। नए मामलों के 30 से 40 हजार के बीच रहना चिंता का कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में करीब ढाई हजार की कमी आई है और वर्तमान में कुल सक्रिय मामले 3,67,415 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 1.14 फीसद है।

संख्या के मामले में 148 दिन बाद और प्रतिशत के हिसाब से पिछले साल मार्च के बाद सक्रिय मामले सबसे निचले स्तर पर पहुंचे हैं। हालांकि, इस दौरान नए मामले 35 हजार से ज्यादा पाए गए हैं, जिनमें से 21 हजार से ज्यादा अकेले केरल से हैं। 440 लोगों की जान भी चली गई है। वैसे मरीजों के उबरने की दर में सुधार ही हुआ है और मृत्यु दर में कोई बदलाव नहीं आया है। साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर भी तीन फीसद से नीचे ही है। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की 56 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें करीब 44 करोड़ पहली और 12 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज शामिल हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अब तक छह करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 57.88 करोड़ डोज मुहैया कराई गई हैं।

एक नज़र...

एलओसी पर दो भाइयों समेत तीन पाक नाबालिग गिरफ्तार

जमू, (एजेंसी)। भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के गुलपुर सेटर में भारती क्षेत्र में घुस आए तीन नाबालिग पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। पुंछ जिले के चक्कां दा बाग क्षेत्र में शून्य रेखा के पास दबोचे गए तीन में से दो सगे भाई हैं। इनकी पहचान धनयाल मलिक (17) पुत्र मोहमद नियाज अली निवासी गांव लस्सीमंग छातरा जिला फरवर्ड कोहटा, अरबाज रहीम (13) पुत्र अदुल रहीम और उसका भाई उमर रहीम (9) के रूप में हुई है। तीनों पाकिस्तान अधिकृत जमू-कश्मीर के बताए जा रहे हैं।

चौटाला ने दी 10वीं की परीक्षा, बोले- आई एम स्टूडेंट, नो कमेंट्स

सिरसा, (एजेंसी)। पूर्व मुयमंत्री ओपी चौटाला बुधवार को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा देने सिरसा पहुंचे। जब उन्हें देख मीडियाकर्मी आगे आए तो उन्होंने कहा कि आई एम स्टूटेंड, नो कमेंट्स। पूर्व सीएम विद्यार्थी की तरह पेपर देने आए और किसी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया। ओपी चौटाला ने शिक्षा विभाग से राइटर की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए विभाग ने उन्हें राइटर उपलध करवाया। दो घंटे में परीक्षा देकर ओपी चौटाला परीक्षा केंद्र से रवाना हो गए।

ईडी निदेशक के सेवा विस्तार मामले में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने ईडी के मौजूदा निदेशक के सेवाविस्तार से संबंधित याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कार्यकाल के लिए किए गए प्रावधान से कहीं भी पता नहीं चलता कि ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं हो सकता है।

मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में आप की किस तरह के विषयों में रुचि है। इन विषयों को आप माई गव या नमो एप पर साझा कर सकते हैं। आप फोन नबर 1800117800 पर अपना संदेश रिकार्ड करके भी भेज सकते हैं।

हरियाणा में 'गोरख धंधा' शद पर प्रतिबंध

चंडीगढ़ । गलत कार्यों के लिये असर इस्तेमाल होने वाला 'गोरख धंधा' शद का इस्तेमाल अब हरियाणा में नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के मुयमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गोरखनाथ समुदाय के लोगों ने बुधवार को यहां मुलाकात कर इस शद पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। समुदाय के लोगों का मानना है कि इस शद के इस्तेमाल संत गोरखनाथ के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। मुयमंत्री ने कहा कि गुरू गोरखनाथ एक संत थे और 'गोरखनाथ' शद का किसी आधिकारिक भाषा, वार्तालाप, भाषण या किसी अन्य संदर्भ में इस्तेमाल इस समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करता है।

तेजस्वी, मीसा, सदानंद और मदन मोहन झा पर केस

पटना । बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और विधान पार्षद एवं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा समेत छह लोगों के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट के एक वकील ने बुधवार को पटना के सीजेएम कोर्ट में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों के साथ एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया।

सूचना आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नगालैंड और तेलंगाना समेत कई राज्य सूचना आयोग में खाली पदों और सूचना आयोग में लंबित अपील के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी. कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में खाली पदों को नहीं भरने पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोग के 11 पदों में से 4 पद खाली हैं. साथ ही निर्देश दिया कि तीन हफ्ते में सभी पदों को भरा जाए. आदेश का अनुपालन नहीं होने पर मुख्य सचिव के खिलाफ समन जारी होगा.

पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर रिपोर्ट देने को कहा था. कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग की राज्य समितियों और केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने कहा था कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों की जानकारियां 4 सप्ताह के भीतर देनी होगी और साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी.

इस याचिका में कानून के तहत सीआईसी और एसआईसी में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है. भारद्वाज ने सरकारी प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया. कोर्ट ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि सीआईसी में अब भी तीन रिक्तियां हैं और सरकार को मौजूदा स्थिति की जानकारी देनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को सीआईसी और आईसी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों को छांटने के लिए मानदंड और मौजूदा रिक्तियों एवं पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के नाम जैसी जानकारी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईसी में रिक्तियां हैं और इस कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है.

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू सर एम. विश्वेश्वरैया स्मृति पुरस्कार एम.एस.रमैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एम.आर. जयराम को प्रदान करते हुए, कर्नाटक के राज्यपाल, श्री थावरचंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, श्री बसवराज बोम्मई भी दिखाई दे रहे हैं।

आयुष्मान भारत के तहत इलाज पाने वाले लाभार्थियों की संया पहुंची 2 करोड़

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा करने की उपलब्धि हासिल कर ली है. स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस योजना से गरीब लोगों को अब तक 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ है. देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को इस योजना के तहत 2 करोड़ लोगों के इलाज पूरा होने की उपलब्धि के अवसर पर कहा कि ये वही लोग हैं जो गरीबी की वजह से अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा पाते थे. जिन 2 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराके इस योजना के तहत इलाज मिला है, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे थे जिनमें जान भी जा सकती थी. इस योजना ने बहुत सारे लोगों को नया जीवन दान देने का काम किया है

23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी–बता दें कि 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की थी.

उस वक्त पीएम ने कहा था कि इस योजना के जरिए हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, जहां हर नागरिक स्वस्थ्य हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च नागरिकों पर बोझ न बने.

स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर कही यह बात– मांडविया ने कहा, 'जब यह योजना को लॉन्च किया गया था तो उस वक्त तक बहुत सारे लोगों की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं था. लेकिन, यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ऐसी योजना की परिकल्पना की और इसे लागू किया. आज जब पूरी दुनिया के साथ-साथ हमारा देश भारत भी कोविड-19 महामारी की मार झेल रहा है तो ऐसे में इस योजना की उपयोगिता अब हर कोई महसूस कर रहा है.

मांडविया ने आगे कहा कि PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. इसके लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से अधिक है. भारत जैसे देशों में देखा गया है कि हेल्थकेयरर पर होने वाला खर्च सामान्य परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है. खासकर गरीब परिवारों के लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है. महिलाओं को अपना जेवर गिरवी रखना पड़ता है. हम सबने देखा-सुना होगा कि लोगों को इलाज के लिए अपनी जमीन-जायदाद तक बेचनी पड़ती है. जिंदगी भर की बचत एक झटके में बीमारी छिन लेती है. प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू हुई इस योजना ने ऐसे लोगों का दुख-दर्द दूर करने का काम किया है.

बता दें कि आयुष्मान कार्ड जितने लोगों को मिले हैं, उनमें से तकरीबन 50त्न महिलाएं हैं. जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनमें 47त्न महिलाएं हैं. PM-JAY के तहत 141 ऐसे medical procedures शामिल किए गए हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं. महिलाएं सिर्फ इस योजना की लाभार्थी ही नहीं हैं बल्कि इस योजना के क्रियान्वयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. ग्रामीण भारत में आशा वर्कर और अस्पतालों में आरोग्य मित्र से लेकर राज्य की कई हेल्थ एजेंसियां की प्रमुख के तौर पर भी महिलाएं इस योजना के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रही हैं.

कोरोना महामारी के बाद बड़ी उपलब्धि हासिल की– मांडविया ने इस मौके पर कहा, 'अब तक इस योजना के तहत तकरीबन 16.50 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं. यह उपलब्धि तब हासिल की गई है, जब पिछले डेढ़ 1.5 साल से कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं. आयुष्मान भारत PM-JAY आने वाले दिनों में और बढ़े और जन भागीदारी से एक mass movement का रूप ले. हमें यह सोचना चाहिए कि इसके क्रियान्वयन में इसके बारे में जागरूकता फैलाने में समाज के अलग–अलग वर्गों का सहयोग हम कैसे ले सकते हैं. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे जुड़ी दो और योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यूपीए पर फोड़ा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के हवाले करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि ईंधन के दाम तब स्थिर होंगे जब सभी पक्षकार जरूरी कदम उठाएं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में संवेदनशील है और कदम उठा रही है. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी ने यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपये उत्पाद शुल्क लेती है और इससे होने वाली कमाई को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पेट्रोल-डीजल की कीमतों से अधिक चिंतित है तो उसे अपने शासन वाले राज्यों में इन ईंधनों पर लगने वाले वैट (मूल्य वर्धित कर) को कम कर देना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2010 में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने ही पेट्रोल व डीजल को नियंत्रण से मुक्त किया था जिससे इन ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुताबिक तय होती हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें प्रतिशत में वैट लगाती हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर वैट भी बढ़ जाता है. पुरी ने दावा किया कि कांग्रेस नीत गत सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों को नियंत्रित करने के लिए 1.34 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड जारी किए और यह समस्या राजग सरकार को विरासत में मिली. उन्होंने कहा कि इस बांड की वजह से हमें इस साल भी 20 हजार करोड़ रुपये देने थे. पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मंत्री ने कहा, 'हम इस विषय पर संवेदनशील हैं और हम अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं जैसे बायो फ्यूल की ब्रांडिंग करना.'

'सुनंदा की मौत के मामले में न्याय हुआ, मुझे कई निराधार आरोप झेलने पड़े': शशि थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत द्वारा आरोपमुक्त किये जाने के बाद बुधवार को कहा कि उनके साथ न्याय हुआ है, हालांकि उन्हें निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा. दिल्ली की एक अदालत ने थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की यहां एक होटल में हुई मौत के मामले में बुधवार को आरोपमुक्त कर दिया.

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. थरूर ने न्यायाधीश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते साढ़े सात साल 'प्रताड़ना' में बीते और यह फैसला 'बड़ी राहत' लेकर आया है. इस

फैसले के बाद थरूर ने एक बयान जारी कर कहा, ''मैं न्यायाधीश गीतांजलि गोयल जी का उनके फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. इस फैसले से उस दुःस्वप्न की परिणति हुई जिससे मुझे अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के निधन के बाद गुजरना पड़ा.''

थरूर के मुताबिक, ''मुझे कई निराधार आरोप झेलने पड़े और मीडिया की ओर से भी बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे न्यायपालिका में पूरा विश्वास था. मेरे रुख की आज पुष्टि हुई है.'' उन्होंने कहा, ''हमारी न्यायिक प्रणाली में प्रक्रिया ही अक्सर सजा बन जाती है।

बहरहाल, तथ्य यह है कि न्याय हुआ है और हमारा पूरा परिवार को सुनंदा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा. '' उन्होंने अपने वकीलों का धन्यवाद किया. सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत मिली थीं. दंपति होटल में ठहरे हुए थे क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था.

पीएम मोदी-अमित शाह पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का निशाना, कहा- 'दोनों ने उत्तर पूर्व में फैलाई अराजकता'

नई दिल्ली। असम और मिजोरम बॉर्डर पर बने हालातों को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी और गृह मंत्री ने मिलकर पूरे उत्तर पूर्व में अराजकता फैला दी है. दोनों ने मिलकर पूरे उत्तर पूर्व को हिंसा की आग में झोंक दिया है. ये आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. ये दोनों नार्थ ईस्ट में आपराधिक समझौता करने के दोषी हैं. उन्होंने कहा कि नार्थ ईस्ट में सैवेधनिक ढांचे पर प्रहार हो रहा है. यहां स्थिति खतरनाक बन गई है. कानून व्यवस्था पूरी टूट चुकी है. राज्यों के बीच देशों में दुश्मनी जैसे हालात हो रही हैं.

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये हिंसा और टकराव मोदी सरकार की नाजायज सरकार हथियाने की भी मंशा है चाहे उसके कोई भी परिणाम हो. पीएम ने अपनी सैवेधनिक जिम्मेदारी से मुह मोड़ लिया है. क्या पीएम और गृह मंत्री जवाब देंगे कि असम और मिजोरम बॉर्डर पर हो रही हिंसा में जो मौतें हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है. दोनों राज्यों ने आने-जाने पर पाबंदी लगा दी. बीते दिन यानी 17 अगस्त को एक बार फिर असम और मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग हुई. उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों को गोलियां लगी, जिससे बॉर्डर पर तनाव है.

'मेघालय में हालात और ज्यादा खतरनाक'– मेघालय का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जो मेघालय में जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है. वहां भी एनडीए की सरकार है. यहां ्च47 लेकर शिलॉग में तालिबान जैसे काले झंडे लेकर उग्रवादी दिखाई दिए. मेघालय के सीएम के घर पेट्रोल बम फेंके गए. शिलॉग में कर्फ्यू लगाना पड़ा और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया. मेघालय के राज्यपाल जब वापस आ रहे थे तो उनके काफिले पर भी पत्थर बरसाए गए.

उन्होंने कहा सत्ताधारी दल और तालिबान का रिश्ता पुराना है. इस दौरान उन्होंने द्बष्814 का हाइजेक का भी जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि मौलाना मसूद अजर और अन्य आतंकवादियों को छोड़ के आए थे इसपर बात क्यों नहीं की जाती है. दोहा में क्या बात करने के लिए गुप-चुप तरीके से कोई इंडियन डेलिगेशन भेजा गया था. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति गंभीर है. हमको अपने हितों की रक्षा करनी है.

बदमाशों ने वाहनों को निशाना बनाकर पथराव किया है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है.प्रतिबंधित उग्रवादी समूह हिनीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी) के पूर्व नेता चेस्टरफील्ड थांगख्यू की मौत के बाद से मेघालय में पिछले कुछ दिनों से अशांति का माहौल है. थांगख्यू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया.

काबुल की ऊंची इमारतें और चकाचौंध देखकर हैरान हैं युवा तालिबान लड़ाके, आका से वापस नहीं जानें की जिद की

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा करने वाले हजारों तालिबान लड़ाकों में से एक 22 साल के एजानुल्ला ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। काबुल की पक्की सड़कों पर ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट, इमारतों में शीशे के कार्यालय और शॉपिंग मॉल उसे अचम्भे में डाल रहे थे। गृह मंत्रालय के भीतर उम्दा फर्नीचर के बारे में उसने कहा कि वह ऐसा था जैसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एजानुल्ला ने कहा कि वह अपने कमांडर से पूछेगा कि क्या उसे यहां रहने की अनुमति मिलेगी। उसने कहा, 'मैं वापस नहीं जाना चाहता।' आज का काबुल और अन्य शहर वैसे नहीं हैं जैसे 20 साल पहले के तालिबान शासन में थे जिसके लड़ाके मुख्यतः ग्रामीण इलाकों से आते हैं।

अफगानिस्तान की एक पूरी पीढ़ी आधुनिकता और पश्चिमी विकास के रंग में रंगी हुई है। बहुत से लोगों को डर है कि इतने सालों में जो हासिल किया है वह तालिबान के वापस आने के बाद कहीं फिर से न खो जाए। जब दो महिलाओं ने एजानुल्ला को सड़क पर हैलो कहा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, 'उन्होंने कहा कि वे हमसे डरती थीं और सोचती थीं कि हम डरावने हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी बहनों की तरह हो और हम तुम्हें स्कूल जाने देंगे शिक्षा लेने देंगे और सुरक्षा देंगे। बस तुम अपने हिजाब का ध्यान रखो।' तालिबान सचमुच बदल गया है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता लेकिन यह वो देश नहीं है जिस पर संगठन ने गृह युद्ध के चार साल बाद 1996 में कब्जा किया था। सोवियत संघ की वापसी और 1992 में कम्युनिस्ट समर्थक सरकार के जाने के बाद अफगानिस्तान को गृह युद्ध झेलना पड़ा था जिसके बाद तालिबान का शासन रहा था। उस जमाने में शहर खंडहर की शक्ल में हुआ करते थे जिस पर स्थानीय लड़ाके प्रशासन चलाते थे। ज्यादातर अफगान टूटी फूटी सड़कों, साईकिल या पीली टैक्सी में चला करते थे। पूरे देश में उस समय केवल एक कम्प्यूटर था जो तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के पास हुआ करता था। मजे की बात यह थी कि उसे वह चालू करना तक नहीं आता था। वर्ष 2001 में तालिबान का शासन समाप्त होने और इस साल फिर से बहाल होने के बीच देश में बहुत बदलाव आ चुका है। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में टेलीविजन और गीत संगीत प्रतिबंधित था, लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी थी और महिलाएं घरों के बाहर काम नहीं कर सकती थीं। लेकिन आज देश में चार मोबाइल कंपनियां और कई सेटेलाइट टीवी स्टेशन हैं जहां महिला एंकर काम करती हैं जिनमें से एक ने सोमवार को तालिबान के एक अधिकारी का साक्षात्कार लिया था। स्वयं तालिबान लड़ाकों के हाथों में महंगे मोबाइल फोन देखे गए जिनसे वह सेल्फी लेते नजर आए। तालिबान लड़ाके आधुनिकता के रंग में रंगे काबुल शहर को देखकर हैरान हैं।ऑनलाइन उपलब्ध वीडियो में वे एक मनोरंजन पार्क में मस्ती करते और जिम में देखे गए। तालिबान के कब्जे के बावजूद राजधानी में ही रूकने का फैसला करने वाले देश के लोकप्रिय टोलो टीवी नेटवर्क के मालिक साद मोहसेनी ने कहा कि बहुत से अफगान लोगों को तालिबान के वेश में लुटेरों का डर सता रहा है। उन्होंने कहा, '' ये तालिबान का रूप धरने वाले लुटेरे अधिक खतरनाक हैं क्योंकि ये केवल लफंगे हैं।

सार समाचार

महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने से पाकिस्तान में सिख समुदाय नाराज

पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर में सिख समुदाय ने कहा है कि लाहौर किला में लगे सिखों के प्रथम शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा की पंजाब प्रांत के अधिकारी अगर रक्षा नहीं कर सकते तो वे प्रतिमा को यहां लाएंगे। प्रतिमा को एक कट्टरपंथी युवक ने तोड़ दिया। प्रतिबंधित तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के एक कार्यकर्ता ने महाराजा रणजीत सिंह की नौ फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा मंगलवार को तोड़ दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक वीडियो में दिख रहा है कि वह नारे लगा रहा है, प्रतिमा का हाथ तोड़ रहा है और घोड़े से सिंह की आवक्ष प्रतिमा को गिरा रहा है। पेशावर में सिख समुदाय के नेता गोरपाल सिंह ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार अगर प्रतिमा की रक्षा नहीं कर सकती है तो वे इसे शहर में लाएंगे। सिंह ने कहा कि सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रतिमा पेशावर लाने के लिए लाहौर जाएगा। उन्होंने कहा कि पेशावर के ऐतिहासिक बालाहिसार किले में रणजीत सिंह की एक तस्वीर करीब छह वर्ष पहले लगाई गई थी और यह अभी तक सही सलामत है जबकि पंजाब सरकार एक प्रतिमा की रक्षा नहीं कर पा रही है। सिंह ने कहा कि प्रतिमा पर बार-बार हमला होने से समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं।

तालिबानियों के विरोध में लोगों ने उठाई आवाज, हिंसक कार्रवाई में तीन की मौत

काबुल। पूर्वी शहर जलालाबाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान की हिंसक कार्रवाई में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए।अफगानिस्तान के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। दर्जनों लोगों ने बुधवार को अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तालिबान का झंडा उतार दिया। इसके बाद तालिबान ने गोलियां चलाईं और लोगों के साथ मारपीट की। स्वास्थ्य अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

जेल से रिहा अफगान तालिबानी हजारों की संख्या में पाकिस्तान में कर रहे प्रवेश

चमन (पाकिस्तान)। इस सप्ताह की शुरूआत में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व में स्पिन बोल्डक/चमन सीमा पार से हजारों की संख्या में अफगानी पाकिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। इनमें चिकित्सा की मांग करने वाले मरीज और मुक्त किए गए तालिबान कैदी शामिल हैं। अफगानी यात्रियों और अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि मंगलवार को, सभी अफगानों के लिए वैध पहचान दस्तावेज या पाकिस्तान में पंजीकृत अफगान शरणार्थी होने का प्रमाण लेकर सीमा खुल गई हैं। सीमा के अफगान क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की शिकायत करते हुए, कई लोगों ने बुजुर्ग रिश्तेदारों या अन्य लोगों के साथ यात्रा की, जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। सीमा पर एकत्र हुए लोगों में से कई ने अल जजीरा को बताया कि वे तालिबान द्वारा अफगान जेलों से रिहा किए गए रिश्तेदारों को प्राप्त करने के लिए वहां आए हैं। इस दौरान अफगान तालिबान के सफेद झंडे हवा में लहरा रहे थे। रिश्तेदारों ने लौटने वाले लड़ाकों का स्वागत किया।

काबुल हवाईअड्डा अब नागरिकों के हवाई सफर के लिए खुला

काबुल। अमेरिका ने कहा है कि काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा सुरक्षित है और अब सभी नागरिकों के हवाई यात्रा के लिए खुल गया है। सेंटकॉम के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सेना के सुदृढीकरण और अपने नागरिकों और उनके अफगान सहयोगियों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका अब हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर रहा है। अफगान मीडिया ने बताया कि सेंटकॉम के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी, जो इस क्षेत्र में एक वरिष्ठ अमेरिकी कमांडर हैं, उन्होंने दोहा में तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें निकासी और सुदृढीकरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए आगाह किया। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी तालिबान को चेतावनी दी थी कि अगर वे काबुल में किसी अमेरिकी सैन्यकर्मी या नागरिक पर हमला करते हैं तो तालिबान को त्वरित और जबरदस्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। काबुल में अधिकारियों ने अभी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैकेंजी ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा वर्तमान में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि काबुल में दूतावास को नागरिकों, भागीदारों, कमजोर अफगानों और एसआईवी के आवेदकों को निकालने के लिए उनका पूरा समर्थन होगा।

तिब्बत में ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय में 12.5 प्रतिशत का इजाफा

बीजिंग। 2012 से अब तक चीन में ग्रामीण गरीब आबादी में 8.5 लाख की कमी आयी है। 2012 से 2020 तक तिब्बत में ग्रामीण निवासियों की औसत आमदनी में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि आयी, जो 5,698 युआन से बढ़कर 14,598 युआन तक पहुंच गयी है। तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के स्थायी उपाध्यक्ष बाईमावांगत्वेई ने 17 अगस्त को तिब्बत में आयोजित एक न्यूज ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तिब्बत में गरीबी उन्मूलन कार्य करने से तिब्बत ने उद्योग के विकास को गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता मानी, साथ ही रोजगार के मौके को बढ़ाने, शिक्षा को महत्व देने और न्यूतम जीवन गारंटी प्रणाली को सुनिश्चित देने आदि विविध कदमों से लोगों को गरीबी से छुटकारा पाने में मदद दी। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से 2020 तक तिब्बत में ग्रामीण उपभोक्ताओं की खुदरा बिक्री की कुल रकम 5.36 अरब युआन से बढ़कर 1.3 खरब युआन तक पहुंच गयी, जिस की औसत वार्षित दर 11.8 प्रतिशत है। हाल में तिब्बती लोगों में खुशी और सुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है।

तालिबान समर्थक इमरान सरकार ने खूंखार आतंकवादी मुल्ला मोहम्मद रसूल को किया रिहा

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में तालिबानियों की वापसी का पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने समर्थन किया था और अब तालिबानियों को खुश करने के लिए एक आतंकवादी को रिहा कर दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान के मुल्ला मोहम्मद रसूल को रिहा कर दिया है। पिछले पांच सालों से मुल्ला मोहम्मद रसूल पाकिस्तान की जेल में कैद था लेकिन अब उसे आजाद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से अलग होने के बाद मुल्ला मोहम्मद रसूल ने अपना अलग संगठन बना लिया था। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकवादियों की मौज हो गई है। पिछले एक सप्ताह में तालिबानियों ने 2,300 आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। इन आतंकवादियों को काबुल, कंधार और बगराम जेल से रिहाई मिली है और अब पाकिस्तान भी तालिबान के समर्थकों को रिहा कर रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण किए जाने का समर्थन करते हुए दिखे और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अफगानिस्तान में लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष रविवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया और राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया।

अफगानिस्तान में तालिबानियों के हाथ नहीं लगा मुद्रा भंडार, देश में विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं

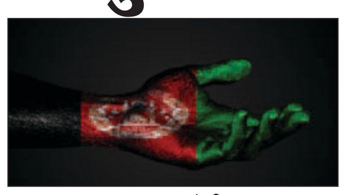

काबुल। (एजेंसी)।

तालिबानियों ने आश्चर्यजनक गति से अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उग्रवादियों को अफगान केंद्रीय बैंक की जमा संपत्ति हाथ नहीं लग पाएगी। एक अफगान अधिकारी के अनुसार, देश के केंद्रीय बैंक, दा अफगानिस्तान बैंक (डीएबी) को अपने तिजोरी में विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य खजाने रखने के लिए जाना जाता है। बैंक के कार्यवाहक गवर्नर अजमल अहमदी, जो काबुल से भाग गए हैं, सहित अफगान अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश संपत्ति अफगानिस्तान के बाहर रखी गई है, संभावित रूप से उनमें से अधिकांश को विद्रोहियों की पहुंच से बाहर रखा गया है। इसके कारण तालिबानियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है।

तालिबानियों के हाथ नहीं लगी विदेशी मुद्रा

अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश का करीब नौ अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में है। उन्होंने कहा कि देश में नकदी के तौर पर कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख अजमल अहमदी ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की करीब नौ अरब डॉलर की राशि में से सात अरब डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बांड, संपत्तियों और सोने में जमा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के पास अमेरिकी मुद्रा का भंडार 'शून्य'है। उन्होंने कहा कि तालिबान द्वारा देश पर कब्जे के बीच देश को नकदी का भंडार नहीं मिल पाया है। उन्होंने लिखा है कि नकदी की अगली खेप नहीं आ पाई। गवर्नर ने कहा है कि अमेरिकी डालर की कमी से अफगानिस्तान की मुद्रा का मूल्य गिरेगा और महंगाई बढ़ेगी। इसका सीध असर गरीब जनता पर पड़ेगा।

तालिबान ने 'आम माफी' की घोषणा की

तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में 'आम माफी' की घोषणा की और महिलाओं से उसकी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। इसके साथ ही तालिबान ने लोगों की आशंका दूर करने की कोशिश है, जो एक दिन पहले उसके शासन से बचने के लिए काबुल छोड़कर भागने की कोशिश करते दिखे थे और जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा होने के बाद कई लोग मारे गए थे। वहीं, काबुल हवाई अड्डे के नागरिक उड्डयन वाले हिस्से में मंगलवार शाम को तालिबान लड़ाकों के प्रवेश करने और हवा में गोली चलाने की खबर है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला और कई शहरों को बिना लड़ाई जीतने वाला तालिबान वर्ष 1990 के क्रूर शासन के उलट खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई अफगान अब भी आशंकित हैं। पुरानी पीढ़ी तालिबान की अति रूढ़िवादी सोच को याद कर रही है, जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर हमले के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी कार्रवाई से पहले सजा के तौर पर पत्थर से मारने और सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा दी जाती थी। कब्जे के दूसरे दिन काबुल में शांति बनी हुई है और तालिबान गश्त कर रहा है। तालिबान द्वारा जेलों पर कब्जा कर कैदियों को छुड़ाने एवं हथियारों को लूटने की घटना के बाद लोग घरों में ही हैं, लेकिन भयभीत हैं। कई महिलाओं ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के दौरान महिलाओं को और अधिकार देने का पश्चिमी प्रयोग तालिबान के शासन में कायम नहीं रहेगा।

अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद ही तालिबान शासन को मान्यता देने पर निर्णय करेंगे : चीन

बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने बुधवार को कहा कि वह अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद ही देश में तालिबान को राजनयिक मान्यता देने का फैसला करेगा तथा उसे उम्मीद है कि वह सरकार ''खुली, समावेशी और व्यापक प्रतिनिधित्व वाली'' होगी। यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में यह पूछे जाने पर कि चीन तालिबान को राजनयिक मान्यता कब देगा, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, ''अफगानिस्तान के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है।'' उन्होंने कहा, ''यदि हमें किसी सरकार को मान्यता देनी है, तो पहली बात यह है कि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सरकार का गठन नहीं हो जाता।'' उन्होंने कहा, ''हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान में एक खुला, समावेशी और व्यापक प्रतिनिधित्व वाला शासन होगा।

उसके बाद ही हम राजनयिक मान्यता के सवाल पर आएंगे।'' उन्होंने चीन के इस रुख को भी दोहराया कि अन्य गुटों के परामर्श से एक ''खुली और समावेशी'' सरकार बनाने के अलावा तालिबान को किसी भी आतंकवादी ताकतों, विशेष रूप से शिनजियांग प्रांत के उइगर आतंकवादी समूह- ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ईटीआईएम) को अनुमति नहीं देने का अपना वादा निभाना चाहिए। काबुल में तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद के संवाददाता सम्मेलन के बारे में, जिसमें उसने अफगान सरकार के लिए काम करने वालों को आम माफी और महिलाओं के अधिकारों का ''इस्लामी कानून के ढांचे के भीतर'' सम्मान करने की घोषणा की, झाओ ने कहा कि शांति की बहाली इस कट्टरपंथी समूह के लिए सबसे जरूरी काम है। उन्होंने कहा, ''हमने अफगान तालिबान के बयान पर ध्यान दिया है।

हमें उम्मीद है कि वह देश के अन्य गुटों के साथ बातचीत और परामर्श के माध्यम से काम करेगा और एक समावेशी और खुला राजनीतिक ढांचा स्थापित करेगा तथा उदार एवं विवेकपूर्ण घरेलू और विदेश नीति अपनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अफगानिस्तान में अन्य देशों के कर्मचारी और संस्थान सुरक्षित रहेंगे।'' उन्होंने कहा, ''साथ ही, हम उम्मीद करते हैं कि अफगान तालिबान ईटीआईएम सहित आतंकवादी ताकतों से मजबूती से लड़ेगा और चीन के लिए हानिकारक आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए किसी भी बल को अफगानिस्तान की धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने की अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लागू करेगा।'' अल-कायदा का सहयोगी बताया जाने वाला ईटीआईएम चीन के अस्थिर शिनजियांग प्रांत का एक आतंकवादी समूह है। यह प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, जहां एक करोड़ से अधिक उइगर मुसलमान रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने 2002 में ईटीआईएम को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।

इमरान खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानों की आर्थिक मदद के लिए वार्ता करते रहने की अपील की

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनका देश अफगानिस्तान में मौजूदा संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी अफगान नेताओं से संपर्क कर रहा है। खान ने विश्व समुदाय से वार्ता जारी रखने की अपील की, खासकर, लोगों की मदद के लिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था युद्ध में तबाह हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा कि खान को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का टेलीफोन कॉल आया था और दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। खान ने मर्केल से कहा, ÷ पाकिस्तान सभी अफगान नेताओं से संपर्क कर रहा है।'' प्रधानमंत्री ने मर्केल से कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वार्ता करती रहनी चाहिए, खासकर, अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक तौर पर मदद के लिए।

बयान के मुताबिक, खान ने पाकिस्तान और क्षेत्र के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान के अत्यधिक महत्व को भी रेखांकित किया और इस बात पर बल देते हुए कहा कि सभी अफगानों की सुरक्षा के

साथ-साथ अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत अहम है। खान ने रेखांकित किया कि एक समावेशी राजनीतिक समझौता अफगान संकट को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय संगठनों के राजनयिक कर्मियों और कर्मचारियों को निकालने में मदद कर रहा है। मर्केल तीसरी यूरोपीय नेता थी जिन्होंने अफगान संकट पर चर्चा के लिए खान को फोन किया था। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जोनसन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने भी खान को फोन किया था और दोनों कॉल की तवज्जो अफगानिस्तान की स्थिति पर थी।

क्या अशरफ गनी अमेरिका की फिर से लेंगे नागरिकता? राष्ट्रपति बनने के लिए ही तो आए थे अफगानिस्तान

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान की एंट्री के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अशरफ गनी के विमान ने तजिकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी लेकिन लैंड करने की अनुमति नहीं मिलने पर उनका विमान ओमान की तरफ मुड़ गया। बताया जा रहा है कि अशरफ गनी ओमान में हैं और जल्द ही अमेरिका जा सकते हैं।

गनी के पास कहां की है नागरिकता ?

अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में 19 मई 1949 में जन्में अशरफ गनी के पास अमेरिका की भी नागरिकता थी। जन्म के साथ अफगानिस्तान के

नागरिक रहे अशरफ गनी ने 1964 में अमेरिकी की नागरिकता ले ली थी और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। अहमदजई पश्तून जनजाति से ताल्लुक रखने वाले अशरफ गनी ने साल 1983 में कोलंबिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी।

दिसंबर 2001 में 24 साल बाद अफगानिस्तान की जमीं पर वापसी करने वाले अशरफ गनी को राष्ट्रपति हामिद करजई के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में साल 2009 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी क्योंकि अशरफ गनी को साल 2014 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना था। आपका बता दें कि राष्ट्रपति हामिद करजई के बाद अशरफ गनी ने सत्ता संभाली थी जो तालिबान की वापसी के बाद अपना मुल्क ही छोड़कर भाग गए। फिलहाल, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और शांति परिषद प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला सहित कई अफगान नेता काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से वार्ता कर रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अशरफ गनी फिर से अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं ? हालांकि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन अशरफ गनी के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं और अफगानिस्तान में भी अमेरिका के समर्थन से ही उन्होंने सरकार बनाई थी और जल्द ही वह अमेरिका में शरण ले सकते हैं।

अमेरिकी सेना ने अभी तक 3,200 से अधिक लोगों को काबुल से निकाला : व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद अभी तक काबुल से 3,200 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है जिनमें से 1,100 लोगों को तो मंगलवार को निकाला गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया, ''आज अमेरिका के सैन्य विमान 13 उड़ानों से करीब 1,100 अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी के स्थायी निवासियों और उनके परिवारों को लेकर आए। हमें इस संख्या के बढ़ने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा, ''हमने अभी तक 3,200 से अधिक लोगों को बाहर निकाला है जिसमें हमारे कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा हमने अफगानिस्तान के करीब 2,000 विशेष आव्रजकों को भी अमेरिका में नयी जगहों पर बसाया है।'' इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा, ''हम देश से आ रहेसैन्य मालवाहक विमान में औसतन 300 यात्रियों को लाएंगे।'' उन्होंने उन खबरों का जिक्र किया कि काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचने की कोशिश करते हुए कुछ नागरिकों को रोका गया, उन्हें वापस भेजा गया या कुछ को तो पीटा भी गया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग हवाईअड्डे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच, सदन की विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडन से यह वादा करने का अनुरोध किया कि वह काबुल से तब तक लोगों को बाहर निकालना जारी रखेंगे जब तक सभी अमेरिकी नागरिक और उसके सभी अफगान साझेदार सुरक्षित देश से बाहर न आ जाएं।

आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय का किया घेराव

संपत्ति बेचकर अपनी जेब भरना चाहती है एमसीडी

नई दिल्ली (संवाददाता)। भाजपा शासित एमसीडी द्वारा 200 करोड़ रुपए कीमत के नॉवेल्टी सिनेमा की जमीन को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेचने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय का घेराव किया। आप के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि भाजपा जानती है कि आगामी एमसीडी चुनाव में उसकी बुरी तरह से हार होने वाली है। इसलिए वह एमसीडी की प्रॉपर्टी बेच कर अपनी जेब भरना चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि जैसे राज्य में अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई है, वैसे ही एमसीडी में भी 'आप' की सरकार लाएगी। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने जैसे बिजली-पानी की सुविधा देने काम किया है, वैसे ही एमसीडी में भी सुविधाएं दें। नार्थ एमसीडी के एलओपी विकास गोयल ने कहा

कि भाजपा, एमसीडी में घोटाले पर घोटाले करती आई है और अब एमसीडी को पूरी तरह से दिवालिया बना दिया है।

वहीं, एलओपी मनोज त्यागी ने कहा कि आगामी एमसीडी चुनाव में अपनी हार निश्चित मान चुकी भाजपा ने अपनी जेब भरने के लिए 200 करोड़ रुपए के नॉवेल्टी सिनेमा को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। इससे पहले, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता के

दो सौ करोड़ के नॉवेल्टी सिनेमा को 34 करोड़ में बेच दिया : पंकज गुप्ता

नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एमसीडी द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए कीमत के नॉवेल्टी सिनेमा को केवल 34 करोड़ रुपए में बेचने का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी से नॉवेल्टी सिनेमा बेचने का निर्णय वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तब तक पार्टी विरोध करती रहेगी और दिल्ली की जनता को इस भ्रष्टाचार से अवगत कराएगी। आप कार्यकर्ताओं का यह विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा।

भाजपा ने पिछले 15 सालों में दिल्ली की जनता के साथ किया धोखा : कुलदीप

कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर उनको बर्बाद करने का काम किया है। चाहे वह लैंटर की अवैध उगाही का मामला हो, चाहे वो कूड़े के प्रबंधन का मामला हो, हर चीज में भाजपा शासित एमसीडी असफल रही है। अब तो इन्होंने नॉवेल्टी सिनेमा की जमीन, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है, उसको अपने चहेतों को मात्र 34 करोड़ रुपए मे बेच दी है। भाजपा से जब भी बात करो, तब इनके पास अपने कर्मचारी को तनख्वाह नहीं होती है। इनके पास कोई काम करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इनके पास घोटाले और चोरी करने के लिए पैसे होते हैं। इन्होंने पिछले 15 सालों में सिर्फ चोरी की है। इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इन्होंने एमसीडी को सबसे भ्रष्ट विभाग कना कर छोड़ दिया है। अब मुझे लगता है कि इनसे दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है।

भाजपा ने एमसीडी को पूरी तरह से किया दिवालिया : गोयल

आम आदमी पार्टी के नार्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बार-बार मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को अवगत कराती आई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पिछले 15 सालों से घोटाले पर घोटाले करती आई है। चाहे वह दवाई घोटाला हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ों में घोटाला हो, बच्चों के मिड-डे-मील में घोटाला हो। भाजपा ने हर जगह घोटाला करके आज 15 साल में एमसीडी को इस कगार पर लेकर आ गए हैं कि न तो ये कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं और न तो पेंशन दे पा रहे हैं। इसके अलावा, अस्पतालों में दवाई नहीं हैं। बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। भाजपा ने पूरी तरह से एमसीडी को दिवालिया कर दिया है।

दिल्ली के मंत्री ने कहा-ब्रिटेन, अमरिका के इस मॉडल पर काम कर रही है केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में ब्रिटेन और अमेरिका के विकास मॉडल पर आधारित नीतियां तैयार कर रही है. किसी भी देश के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा अति आवश्यक है, जिसके कारण ही विकासशील देश विकसित हो पाए है.

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं मुफ्त जन सुविधाएं प्रदान करने की महत्वकांक्षा को वास्तविकता बना रही है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली के जन समर्पित और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मॉडल ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया है. सत्येंद्र जैन ने अलीपुर गांव नरेला में एक बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया. इस मौके पर नरेला के विधायक शरद कुमार चौहान सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. जैन ने कहा कि सरकार केंद्र को और अधिक बेहतर बनाने की तैयारी भी कर रही है, जो इस गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा यहां के लोगों को किए गए वादे को आज हमने पूरा किया है और हमारा काम ही लोगों के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है. दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है जिसके कारण ही दिल्ली में लगातार दो बार 90 फ़ीसदी सीटें केजरीवाल सरकार को मिलीं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है.

सत्येंद्र जैन ने उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में कहा कि केजरीवाल सरकार जन सुविधाओं को बेहतर और मुफ्त उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने वाली देश की पहली सरकार है. हम स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा में हर गुजरते दिन के साथ उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं. राजनेताओं को देश की प्रगति के लिए चुना जाता है और उनका अपनी सेवा में निस्वार्थ होना आवश्यक है. हमारे भ्रष्टाचार मुक्त और जन समर्पित शासन मॉडल ने लोगों को उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे अपने अधिकारों के लिए जागृत किया है.

संक्षिप्त खबर

दिल्ली में बॉलीवुड फिल्म को लेकर कार्यशाला सम्पन्न

नई दिल्ली। आजकल के युवाओं में टैलेंट गजब का भरा हुआ है बस जरूरत है एक मंच मिलने की। बहुत कम लोग मिलते है जो एक्टिंग की बारीकियों को सही से समझा सकते है और नए टैलेंट को उभार सकते है, यह कहना था क्रिएटिव डायरेक्टर सुनील पराशर का जो कई फिल्मों से जुड़े हुए है एवं कई अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं उन्होंने आगे कहा कि फिल्म निर्माता आदित्य वर्मा जलज जो कि दिल्ली में 3 फिल्में बनाने जा रहे है जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में 3 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें मुझे नए उभरते हुए टैलेंट को चुनने का मौका मिला।

क्यूमैथ 141 शिक्षकों को करेगा सम्मानित

नई दिल्ली। मैथ्स और कोडिंग के लाइव क्लास प्रोग्राम के लिए विख्यात क्यूमैथ ने संस्थान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन शिक्षकों को मारुति सुजुकी बलेनो कार तोहफे के तौर पर देने का निर्णय लिया है। यह सम्मान पाने वाली शिक्षिकाओं में शिक्षिका शालिनी श्रीवास्तव, शिक्षिका यास्मिन बानू और शिक्षिका मंजू चंडक का नाम शामिल है। ये शिक्षिकाएं गाजियाबाद, त्रिची और पुणे ब्रांच में कार्यरत हैं। कंपनी ने यह कदम शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान को अभिव्यक्त करने के मकसद से उठाया है। फाउंडर एंड सीईओ, क्यूमैथ मनन खुर्मा ने कहा की हम क्यूमैथ पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 शिक्षकों को दिल से बधाई देते हैं। शिक्षक और छात्र क्यूमैथ समुदाय के दो सबसे ज्यादा प्रासंगिक स्तंभ हैं। हम सदैव उनके कठिन परिश्रम को महत्व देते हैं। हमें उनकी उपलब्धियों में असीम गर्व की अनुभूति होती है। हमारे शिक्षकों ने महामारी के दौरान भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल रोमांचक, व्यक्तिगत और निरंतर सीखनेके लिए किया। शिक्षकों ने छात्रों को व्यस्त रखने के लिए नए और अभिनव तरीके ईजाद किए और वास्तविक जीवन के अप्रयोगों से सीखने के सत्र को वास्तविक बनाए रखा। यह पुरस्कार उनकी उपलब्धियों और प्रयासों के लिए प्रशंसा का एक छोटा सा प्रयास भर है। शिक्षिका शालिनी श्रीवास्तव करीब 10 हजार ट्यूटर्स में से एक हैं,जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान शिक्षण के तरीके को नए तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया। संस्थान से मिले सम्मान खुशी जाहिर करते हुए शालिनी ने क्यूमैथ के साथ अपने सफर के अनुभव पर कहा,'जब मेरी बेटी हुई तो मैंने अपने 13 साल के टीचिंग करियर में एक ब्रेक लिया। जल्द ही पांच साल बीत गए।

पूर्वी निगम द्वारा हिन्दी प्रतियोगिता का आयोजन

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग द्वारा बुधवार को पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में हिन्दी प्रतियोगिता-2021 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त, शिल्पा शिंदे, अपर उपायुक्त, के.डी. वर्मा और राजभाषा विभाग की प्रभारी, शोभा अरोड़ा व वरिष्ठ निगम अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली भाजपा के सदस्यों ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़े जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

रेलिगेयर फिनवेस्ट घोटाला- 200 करोड़ की ठगी के मामले में रोहिणी जेल के 2 कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली। फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी की शिकायत पर 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस) ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में 2 रोहिणी जेल के कर्मचारी हैं. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि एक शख्स ने खुद को गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर उन्हें पति के मामले में मदद का भरोसा दिलाया और 200 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. इस मामले में एक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. सुकेश की निशानदेही पर ही 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. मामले की जांच जारी है.

दिल?ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में दो आरोपियों को रोहिणी जेल से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि सुकेश से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उन?होंने दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी. जांच अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश जारी है. बता दें कि पहले स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया था और सुकेश और उसके साथी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया था.

शिविंदर सिंह और उनके बड़े भाई मालविंदर मोहन सिंह जो रैनबैक्सी, फोर्टिस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर हैं, को अक्टूबर 2019 में आर्थिक अपराध शाखा ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. ईडी ने बाद में शिविंदर और उसके साथी को 12 दिसंबर, 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया. शिविंदर को जमानत मिल गई थी, हालांकि एक अन?य मामले में वह न्यायिक हिरासत में है.

आंकड़ों में जानिए डीयू एडमिशन का पूरा लेखा जोखा, सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं सबसे आगे

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हैं. रजिस्ट्रेशन अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हुआ था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 3,18,158 स्टूडेंट्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराया है. इनमें से 1,47,435 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के बाद सफलतापूर्वक भुगतान भी कर दिया है. बता दें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है. रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पहली कट-ऑफ सूची 1 अक्टूबर तक जारी करने की संभावना है.

डीयू में एडमिशन के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक संख्या सीबीएसई स्टूडेंट्स 1,21,796 की है. इसके बाद आईएससी बोर्ड के 4,817 स्टूडेंट्स, हरियाणा बोर्ड के 4,723 स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश बोर्ड के 2,984 स्टूडेंट्स हैं. जबकि आवेदकों की सबसे कम संख्या हिमाचल प्रदेश बोर्ड से 335 है. वहीं इस साल डीयू में प्रवेश के लिए सबसे अधिक आवेदन करने वाले 20,398 स्टूडेंट्स दिल्ली-एनसीआर से हैं, जबकि सबसे कम संख्या कटक और शिलांग से क्रमश- 10 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है.

रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के मामले में आगे हैं लड़कियां- रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स में से 1,47,435 स्टूडेंट्स ने सफलतापूर्वक भुगतान भी कर दिया है. भुगतान करने वालों में पुरुष आवेदकों की संख्या 65,507 जबकि महिला आवेदकों की संख्या 82,155 है.

इसके अलावा, विश्वविद्यालय को पाठ्येतर गतिविधियों की श्रेणी के तहत 8,333 और खेल के तहत 5,187 आवेदन मिले हैं. गौरतलब है कि इस वर्ष भी विश्वविद्यालय कोविड -19 महामारी के बीच परीक्षा का आयोजन नहीं कर रहा है. ऐसे में डीयू यूजी प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को हर एक अपडेट के लिए डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.

श्मशान घाट पर शव ले जाने को दक्षिणी निगम ने खरीदा एसी सुविधा लैस शव वाहन, जानिये कितना देना होगा किराया

नई दिल्ली। साउथ दिल्ली नगर निगम ने आधुनिक सुविधाओं से लैस वातानुकूलित शव वाहन जन सेवा में समर्पित किया. इस शव वाहन का परिचालन दक्षिणी निगम के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा सुभाष नगर स्थित श्मशान भूमि का परिचालन करने वाली संस्था के सहयोग से किया जाएगा.

इस शव वाहन को दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सुर्यान, स्थाई समिति के अध्यक्ष कर्नल बी.के. ओबेरॉय, नेता सदन इंद्रजीत सहरावत, स्थायी समिति की उपाध्यक्षा पूनम भाटी, आयुक्त ज्ञानेश भारती, अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय, दक्षिणी दिल्ली के पूर्व मेयर एवं नेता सदन नरेंद्र चावला ने हरी झंडी दिखाकर जनसेवा में समर्पित किया.

मेयर मुकेश सुर्यान ने शव वाहन सुभाष नगर स्थित श्मशान भूमि का परिचालन करने वाली संस्था जन शक्ति को सौंपते हुए कहा कि इस शव वाहन के माध्यम से सच्ची जन सेवा की जा सकेगी ताकि अंतिम समय में शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए परिजनों को निजी शव वाहन चालकों की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा. यह दिवंगत आत्माओं को निगम की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

इसका इस्तेमाल सुभाष नगर स्थित श्मशान घाट पर शवों को लाने के लिए किया जाएगा. इस शव वाहन को वर्ष 2018-2019 के मेयर फंड द्वारा प्रदान की गई राशि से खरीदा गया है. स्थायी समिति के अध्यक्ष कर्नल बी.के. ओबराय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में शवों को श्मशान भूमि तक ले जाने में नागरिकों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था. इस दौरान संक्रमण से काफी लोगों की मृत्यु हुई और शवों को श्मशान तक ले जाने के लिए निजी शव वाहन चालक नागरिकों से मनमाना किराया वसूलते थे.

नागरिकों की इन्ही सब परेशनियों को देखते हुए दक्षिणी निगम ने अपना शव वाहन खरीदा है. इस शव वाहन का इस्तेमाल करने के लिए 500 रुपये का न्यूनतम किराया तय किया गया है और दक्षिणी निगम के क्षेत्र से बाहर अगर कोई नागरिक इस शव वाहन का इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए 800 रुपये किराया होगा.

पीएम के कुशल नेतृत्व की वजह से टीकाकरण की गति तेज- लेखी

नई दिल्ली। भाजपा की तरफ से यमुनापार के तीन जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। नवीन शाहदरा जिले में बाबरपुर बस टर्मिनल से यात्रा की शुरुआत करते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हम लोग जनता के बीच आए हैं। मोदी सरकार वही कर रही है जो जनता चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि टीकाकरण की रफ्तार तेज है। एक दिन में 83 लाख से अधिक लोगों को टीका लगा है।

जनता की पसंद के कारण भाजपा सत्ता में आयी- यह आंकड़ा कई विकसित देशों की आबादी से भी ज्यादा है। यह यात्रा शाहदरा जिले के कई इलाकों से गुजरते हुए मयूर विहार जिले में समाप्त हुई। यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीनाक्षी ने कहा कि आपकी वजह से दो सीटों से शुरू हुई पार्टी आज केंद्रीय सत्ता में है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पार्टी चुनाव जीतती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा था।

विश्वास एवं प्रयास के कारण ही मिली जीत- इसमें उन्होंने अब सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। हमारी पार्टी के जो संकल्प हैं, उसके एक-एक वाक्य को पूरा किया जा रहा है। देश ने बहुत बुरे दिनों में भी जिस साहसपूर्ण तरीके से महामारी का सामना किया वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की देन है। टीकाकरण अभियान इसका उदाहरण है। उन्होंने किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग सिर्फ फोटो चिपकाते हैं। काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का काम बोलता है।

पीएम के नेतृत्व में बढ़ रही देश की ख्याति- भाजपा के प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि यह दिल्ली वालों के लिए गर्व का विषय है कि मीनाक्षी लेखी केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। आज महिला शक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मंत्रिमंडल में जितनी जगह मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली। यात्रा में सांसद गौतम गंभीर, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, वीरेंद्र सचदेवा, तीनों जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, मास्टर बिनोद कुमार, विनोद बछेती आदि मौजूद रहे।

अपने वतन को याद कर छलक उठी अफगान शरणार्थियों की आंखें

नई दिल्ली । अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रह रहे अफगान शरणार्थियों को अपना व अपने देश का भविष्य अधर में दिख रहा है। उनका कहना है कि तालिबान के कब्जे के बाद उनकी वतन वापसी की बची हुई उम्मीद भी टूट गई। अफगान शरणार्थियों ने बताया कि 19 अगस्त यानि बृहस्पतिवार को वह अपने वतन का 102वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे लेकिन तालिबान ने उनके देश को फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया है।

अफगानिस्तान में फंसे अपने परिजनों को वहां सुरक्षित निकालने व विश्व समुदाय से वहां शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बुधवार को सैकड़ों अफगानी शरणार्थी जमा हुए। इस अवसर पर कुछ बच्चे अपने देश का राष्ट्रगान प्रस्तुत कर रहे थे। राष्ट्रगान गाते-गाते बच्चों की आंखें छलक उठीं। अपने वतन को याद कर भावुक हुए कक्षा छह के छात्र यूसुफ ने बताया कि तालिबान के आतंक के कारण उनके पिता को पूरे परिवार के साथ छह साल पहले देश छोड़ना पड़ा था। वहीं, आर्मिला व सना ने बताया कि तालिबानी आतंकियों ने उनके परिजनों की हत्या कर दी दी थी। उसके बाद वे रिश्तेदारों के साथ दिल्ली आ गए। छह साल पहले दिल्ली आई तबस्सुम ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। उन्होंने दिल्ली में 12वीं पास की है। आगे और पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। अफगानिस्तान में फंसे परिजनों की भी चिंता सता रही है। तबस्सुम ने बताया कि उनका देश जब आजाद था तब भी तालिबानियों ने बहुत अत्याचार किए। अब तो वहां की लड़कियों व महिलाओं का भविष्य फिर से अंधेरे में चला गया है। उन्होंने कहा कि भारत में हम लोगों को पूरी सहायता मिल रही है लेकिन अपने देश में अफगानियों को मारा जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों अफगान शरणार्थियों ने अपने देश का राष्ट्रगान गाया और प्रार्थना की कि उनके देश के हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। तीन साल से दिल्ली में रह रहे अब्दुल्ला ने बताया कि मजार-ए-शरीफ में फंसे उनके परिजन भारत आने के लिए वीजा लेने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वीजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं, अफगान शरणार्थियों के प्रतिनिधि रहमत जिया खान ने कहा कि इस कठिन वक्त में यूएनएचसीआर शरणार्थियों की सहायता नहीं कर रहा है।

जागो ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर शिरोमणि अकाली दल की मान्यता रद करने की कि मांग

नई दिल्ली । जग आसरा गुरु ओट (जागो) पार्टी ने भारतीय चुनाव आयोग में याचिका दायर कर शिरोमणि अकाली दल बादल की मान्यता रद करने की मांग की है। जागो पार्टी के अध्यक्ष तथा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने इस संबंध में कहा है कि शिरोमणि अकाली दल की स्थापना गुरुद्वारों के प्रबंध को संभालने तथा पंथक परंपराओं की रक्षा करने के लिए हुई थी। लेकिन, मौजूदा समय में अकाली दल की सियासी विंग धार्मिक प्रबंध पर हावी हो गई है। इस वजह से सिख मुद्दों और सिख कल्याण की अनदेखी हो रही है। इसलिए उन्होंने अकाली दल के धार्मिक चुनाव लड़ने का विरोध किया है और सियासी पार्टी की मान्यता रद करने की मांग की है।

जीके ने कहा कि सिखों को गुमराह किया जा रहा है कि अकाली दल सिर्फ सिख धर्म की बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है। जबकि सच्चाई इसके उलट है। सिखों के ईसाई धर्म में मतांतरण की दर लगातार बढ़ रही है। शिरोमणि अकाली दल का मुख्य सिद्धांत सिख समुदाय को आध्यात्मिक, शिक्षण-पोषण प्रदान करना है।

लेकिन, अब यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से गायब है। गुरुद्वारे में आए धन का उपयोग सिख समुदाय के कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका उपयोग सियासी चुनावों में पार्टी के उत्थान के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संविधान में निर्धारित नियमों के खिलाफ एक राजनीतिक दल के रूप में धार्मिक पार्टी का चुनाव लड़ना भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए खिलाफ है। क्योंकि एक पंजीकृत सियासी दल के अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो धर्म निरपेक्ष निष्ठा का पालन करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।

संपादकीय

दुनिया बदल सकती है यह दोस्ती

जनवरी, 2021 में जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यह तीसरा मौका था, जब अमेरिकी सरकार का कोई वरिष्ठ नेता भारत आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल देर शाम नई दिल्ली से कुवैत की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनसे पहले रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जलवायु परिवर्तन मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी की भारत यात्रा यह संकेत दे चुकी है कि बाइडन सरकार नई दिल्ली को कितनी अहमियत दे रही है।

ब्लिंकन का यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय रिश्तों की दशा-दिशा तय करने वाला माना जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कहीं अधिक मजबूती से मिलकर काम करने की सहमति बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान बातचीत का केंद्र रहा, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से वहां से निकला है, उससे भारत भी चिंतित है। रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा और हवाई जहाज से वे अपने देश के लिए रवाना हुए। भले ही अमेरिका ने अफगान हुकूमत को इसके बारे में स्पष्ट कर दिया था, लेकिन छिपते-छिपाते अमेरिकी फौज की रवानगी कई एशियाई देशों को वियतनाम युद्ध की याद दिला गई। सन 1975 में साइगॉन (हो ची मिन्ह शहर) से अमेरिकी फौज अपने दामन पर हार का दाग लेकर इसी तरह लौटी थी। अफगानिस्तान से उसकी घर वापसी को भी कई देश इसी रूप में देख रहे हैं। भारत के साथ दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे के निर्माण और व्यापार परियोजनाओं में उसने तकरीबन तीन अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने वहां के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं। चूंकि वहां अब तक कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं हो सका है और तालिबान अपने प्रभाव क्षेत्र के लगातार बढ़ने का दावा कर रहा है, इसलिए नई दिल्ली इन विकास-कार्यों के भविष्य को लेकर चिंतित है। एक तर्क यह दिया जा सकता है कि तालिबान शायद इन परियोजनाओं को नुकसान न पहुंचाए, मगर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के बारे में दुष्प्रचार कर रहा है और अमेरिकी फौज की वापसी को भारत की हार के रूप में दुष्प्रचारित कर रहा है, उससे खतरा यह है कि कहीं पाकिस्तानपरस्त आतंकवादी तालिबान की आड़ में इन विकास-कार्यों के लिए खतरा न बन जाएं। नई दिल्ली वाशिंगटन से यह भरोसा चाहता है कि वह अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बजाय एक ठोस रणनीति के तहत उसकी मदद करता रहे।

भारत और अमेरिका के रिश्ते में 'क्वाड' भी काफी अहमियत रखता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना यह संगठन अभी भले ही वैधानिक जामा नहीं पहन सका है, लेकिन इसने चीन के साथ तनाव बढ़ने पर अपनी सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को तेजी से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। मार्च, 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के शासनाध्यक्ष क्रमशः स्कॉट मॉरिसन, नरेंद्र मोदी और योशीहिदे सुगा ने ऑनलाइन शिरकत की थी। उस बैठक में उन्होंने कोविड-19 टीके को लेकर एक कार्य-समूह का गठन किया था और तय किया था कि जापान की आर्थिक मदद व ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक सहायता से भारत हिंद प्रशांत के देशों के लिए अमेरिकी वैक्सीन की एक अरब खुराक बनाएगा। जॉनसन ऐंड जॉनसन में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से टीका-निर्माण में देरी का आशंका पैदा हो गई है, लिहाजा नई परिस्थिति में इस निर्णय को किस कदर साकार किया जाएगा, इस पर भी ब्लिंटन से चर्चा हुई होगी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले और हिंद प्रशांत के देशों में भारत के शामिल होने के कारण नई दिल्ली वैक्सीन-निर्माण को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखा रही है। भारत हरसंभव उत्पादन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे इसके लिए कच्चे माल की जरूरत है, जो अमेरिका ही मुहैया करा सकता है। वैसे, क्वाड से अमेरिका के हित भी खासा जुड़े हुए हैं। दो महासागरों को समेटने वाला हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के समुद्री हितों को बखूबी पूरा करता है। 2019 में इन महासागरों से 19 खरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी व्यापार गुजरा। संयुक्त राष्ट्र की मानें, तो इस साल दुनिया के कुल निर्यात के 42 फीसदी और आयात के 38 फीसदी उत्पाद यहां से गुजर सकते हैं। स्वाभाविक है, इस कारोबार का एक बड़ा खिलाड़ी अमेरिका होगा।

ब्लिंकन के इस दौरे में हथियारों की खरीद का मसला भी उठा होगा और भारत में कथित मानवाधिकार हनन का भी। मगर ये ऐसे मसले हैं, जो हरेक बातचीत का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इन पर काई खास गंभीरता नहीं दिखाई जाती। अलबत्ता, अमेरिका में भारतवंशियों को होने वाली दिक्कतें अब आपसी बातचीत का मुख्य मसला बनती जा रही हैं। अमेरिका की वीजा नीति पर भारत सवाल उठाता ही रहता है, अब अनिवासी भारतीयों पर होने वाले नस्लीय हमले भी चिंता की वजह बन गए हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ किसी तरह की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बाइडन प्रशासन भी इस दिशा में संजीदा है और अनिवासी भारतीयों ही नहीं, तमाम प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर, ब्लिंकन की यह यात्रा कई मायनों में उल्लेखनीय साबित हुई है। विदेश मंत्री बनने के बाद वह पहली बार भारत आए थे और यहां उन्होंने बाइडन प्रशासन का यह मंत्र दोहराया कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात है कि भारत सरकार की तरफ से भी उन्हें सकारात्मक जवाब मिला है। दोनों देशों की यह जुगलबंदी आने वाले दिनों में वैश्विक व्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित कर सकती है।

प्रवीण कुमार सिंह

विशेषाधिकार सदन संचालन में सुविधा के लिए हैं, न कि आपराधिक कृत्यों के सुरक्षा कवच

लोकसभा नियमावली में संसदीय दीर्घा का संज्ञान लेने पर रोक है। राहुल जी ने दर्शक दीर्घा में बैठे युवकों का ध्यान आकर्षित किया था। कागज छीनने-फाड़ने की घटना ताजी है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या ऐसे कृत्य भी सदन के विशेषाधिकार हैं। केरल विधानसभा मामले में सर्वोच्च न्यायपीठ ने ऐसे कृत्यों को विशेषाधिकार से अलग आपराधिक कृत्य माना है। भारत की विश्व प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन संसद और विधानमंडलों का काम उत्पादक नहीं है। सदनों का व्यवधान राष्ट्रीय चिंता है। पीठासीन अधिकारियों के तमाम सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन परिणाम शून्य हैं।

संसद को सर्वोच्च विधायी अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी संसदीय व्यवस्था को संविधान का आधारिक ढांचा बताया है। संसद के अपने विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार संसद सदस्यों को भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 105(1) में कहा गया है कि 'संविधान के उपबंधों, संसद की प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।' आगे इसी अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लिखित है, 'संसद या संसद की समिति में सांसद द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।' संप्रति विपक्ष के कुछ सांसद विचार स्वातंत्र्य को शोर स्वातंत्र्य मानते हैं। वे हंगामे और व्यवधान को भी संसदीय कार्यवाही का अंग मानते हैं। राष्ट्रीय चुनौतियों और जनहित के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा नहीं होती। संविधान के अनुसार सरकार संसद में जवाबदेह है। सदन में संवाद की ही उपयोगिता है। इसी से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, लेकिन कुछ समय से सदन में बाधा डालने, नियमावली को तार-तार करने का चलन बढ़ा है। संसद का चालू मानसून सत्र भी कोई अपवाद नहीं।

सदन और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार सदन संचालन में सुविधा के लिए हैं, न कि आपराधिक कृत्यों के सुरक्षा कवच। केरल विधानसभा में हुए उपद्रव के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने सही फैसला सुनाया है। केरल सरकार के मंत्री वी शिवनकुट्टी और पांच अन्य सदस्यों ने 13 मार्च, 2015 को बजट में बाधा डाली। विपक्षी सदस्यों के रूप में वे विधानसभा कर्मियों से भिड़ गए थे। उन्होंने सभा की संपदा को क्षति पहुंचाई। इसमें करीब 2.2 लाख

रुपये का नुकसान हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ। मौजूदा केरल सरकार ने उसे वापस लेने की अर्जी लगाई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेषाधिकार और सदन के भीतर हुए उपद्रवों को अलग-अलग बताया है। कहा है कि विशेषाधिकार आपराधिक मामलों से छूट प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। कोर्ट के फैसले में विशेषाधिकार का उल्लेख विचारणीय है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुरेंद्र मोहंती बनाम नवकृष्ण मामले में कहा था 'कोई भी न्यायालय विधानमंडल सदस्य के सदन में दिए भाषण के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता।' हालांकि यहां भाषण की नहीं, बल्कि हिंसा की बात है।

विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसदीय स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा रहा है। न्यायालय सभा की कार्यवाही नहीं जांच सकते, लेकिन आपराधिक कार्यों के संरक्षण के उद्देश्य से अपराध कर्म को विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा के एक सदस्य ने अपने माइक को लाउडस्पीकर से जोड़ने के लिए आपरेटर पर झल्लाकर पेपरवेट फेंका। अध्यक्ष के माइक पर झपट्टा मारा। सदस्य को सभा से निष्कासित किया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दोषी पाया गया। सदन बाहुबल प्रदर्शन का स्थान नहीं है। यह संवाद का श्रेष्ठतम मंच है, लेकिन यहां का दलतंत्र ही सदन में बाधा डालने की योजना बनाता है। सांसदों और विधायकों को हुल्लड़ के निर्देश दिए जाते हैं। संसदीय प्रणाली पर संसद द्वारा प्रकाशित 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का प्राक्कथन पठनीय है। उन्होंने लिखा था 'संसद में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था से मर्यादा क्षीण होती है। नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए। आवश्यक है कि संसद लोगों की नजरों में अपनी अधिकाधिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित ढंग से काम करे।' अभी संसद सत्र में योजनाबद्ध व्यवधानों से गतिरोध जारी है। तमाम माननीय पोस्टर प्लेकार्ड लाते हैं। हंगामा करते हैं। अध्यक्ष/सभापति की बात नहीं सुनते। हाल में एक माननीय के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन निलंबन की निंदा भी हो गई। निलंबन अच्छा नहीं होता। पीठासीन अधिकारी इसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय सरकार ने 63 सदस्यों का निलंबन कराया। तब कांग्रेस ने निलंबन की निंदा भी नहीं की थी। 2014 में भी 16 सांसदों का निलंबन हुआ था। आक्रामक व्यवधान के बीच संसद में व्यवस्था बनाना कठिन है। वेल में आना, मंत्रियों से कागज छीनना पराक्रम हो गया है। ऐसे कृत्य लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध हैं। व्यवधानकर्ताओं को दंडित करने के लिए 2001 में लोकसभा की नियमावली में 374(क) जोड़ा गया था। इसके अनुसार अध्यक्षीय आसन के सामने शोर करने वाले सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम लेते ही स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मगर इसका उपयोग प्रायः नहीं होता। संसदीय व्यवहार का पराभव खतरे की घंटी है। आमजन अपने जनप्रतिनिधियों को शोर मचाते देखकर आहत और निराश हैं। दुनिया के अनेक देशों में संसदीय व्यवस्था है। ब्रेक्जिट मामले को छोड़कर ब्रिटिश संसद में प्रायः व्यवधान नहीं हुए। अमेरिकी कांग्रेस में व्यवधान नहीं होते। जापानी संसद डायट भी खूबसूरत ढंग से चलती है। ऐसे देशों ने अपनी संसदीय व्यवस्था का सही विकास किया। भारत की संविधान सभा की कार्यवाही 165 दिन चली थी। 17 सत्र हुए थे। बहस तीखी थीं, लेकिन व्यवधान नहीं थे। पहली लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा. श्यामा प्रसाद जैसे महानुभाव थे। पहली दफा 1952 में प्रिवेंटिव डिटेंशन संशोधन विधेयक पर व्यवधान हुआ। 1963 में आधिकारिक भाषा विधेयक पर भी तनातनी थी, मगर ऐसे व्यवधान अपवाद थे। 1968 तक व्यवधान नहीं थे, मगर अब वे आम हो गए हैं। संसद में सदन संचालन की सुस्पष्ट नियमावली है। फिर भी हंगामा है। आखिर संसदीय कार्यवाही के मुख्य घटक क्या हैं? कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सदन में आंख मारने का विचित्र कौशल दिखाया था। लोकसभा नियमावली में संसदीय दीर्घा का संज्ञान लेने पर रोक है। राहुल जी ने दर्शक दीर्घा में बैठे युवकों का ध्यान आकर्षित किया था। कागज छीनने-फाड़ने की घटना ताजी है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या ऐसे कृत्य भी सदन के विशेषाधिकार हैं। केरल विधानसभा मामले में सर्वोच्च न्यायपीठ ने ऐसे कृत्यों को विशेषाधिकार से अलग आपराधिक कृत्य माना है। भारत की विश्व प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन संसद और विधानमंडलों का काम उत्पादक नहीं है। सदनों का व्यवधान राष्ट्रीय चिंता है। पीठासीन अधिकारियों के तमाम सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन परिणाम शून्य हैं। संसद ही अपनी प्रक्रिया की विधाता है। गहन आत्मचिंतन ही उपाय है।

चीन और पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों से कुछ सबक सीखने को तैयार नहीं कम्युनिस्ट

यह दिनोंदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि देश की कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने राजनीतिक भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसलिए एक-एक कर दो राज्य उनके हाथ से फिसल गए। इसके बावजूद उनके पास आने वाले दिनों का कोई खाका नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन पार्टियों के शीर्ष प्रतिनिधि हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के 100वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए होते। जिस देश के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है और जो हमारी जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसके देश की पार्टी के कार्यक्रम में जाने से उसे भारत में राजनीतिक रूप से क्या लाभ मिला, यह कोई कामरेड आपको नहीं बता पाएगा। इस बारे में सवाल किए जाने पर वही अहंकार भरा जवाब, आप हमें क्या बताएंगे। हमने तो 35 साल बंगाल में और 25 साल त्रिपुरा में शासन किया है। लगातार दूसरी बार केरल में सत्ता में आए हैं। कहना न होगा कि जो पार्टी भविष्य के बजाय भूत में जीने लगे, उसका तो पतन निश्चित है।

कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी फिक्र होती तो केरल में मार्क्?सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने लव जिहाद, मतांतरण और आतंकवाद जैसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ कोई ठोस रणनीति बनाई और लागू की होती। ऐसा नहीं हुआ है। इसके ठीक उलट केरल इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें इतनी ज्यादा संभावना पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अफगानिस्तान में अपना बर्बर शासन स्थापित करने की ओर बढ़ रहे तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर के अलावा केरल को भी निशाना बनाने की साजिश रच रही है।

ब्रिटेन में रह रहे गुलाम कश्मीर के पत्रकार अमजद अयूब मिर्जा के अनुसार केरल पर पाकिस्तान की नजर अचानक नहीं पड़ी है, बल्कि वह काफी समय से इस पर काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि केरल में हाल ही में अफगानिस्तान में बनी हाई क्वालिटी की ड्रग्स की बरामदगी के मामलों में बढ़ोतरी से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में तालिबान का असर बढ़ रहा है। दो दशक तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद पोश्त और उससे निकलने वाली अफीम की खेती-व्यापार पर तालिबान का ही कब्जा है। उसके लिए धन का बड़ा स्रोत अफीम से बनने वाले ड्रग्स की तस्करी है। इस संबंध में अयूब का पूरा लेख पढ़कर केरल की कम्युनिस्ट सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन वह तो कुछ देखना ही नहीं चाहती है। भारत को अस्थिर करने के लिए कश्मीर में पिछले कई दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहा पाकिस्तान किसी भी सूरत में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पर बिठाना चाहता है। उसके नापाक इरादों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। इसलिए उसने भारत के साथ दिखावे के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है और वहां से सेना हटाकर उन्हें उत्तरी सीमा पर तालिबानियों की मदद में तैनात कर दिया है और भारत में लगातार ड्रोन भेज-भेजकर उसे उलझाए हुए है। केरल सरकार राज्य में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करती है, क्योंकि वही उसके वोटर हैं। वोट की राजनीति के कारण राज्य देश विरोधी तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। देश के अंदर आतंक की जड़ें मजबूत करने वाला यासीन भटकल केरल का ही रहने वाला है। इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद इस आतंकी की इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना में अहम भूमिका थी। देश भर में इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा दे रहा पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) का ठिकाना भी केरल ही है।

कश्मीर के बाद केरल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अगर सच साबित होते हैं तो भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य बलों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होती। यह छद्म युद्ध का एक और मोर्चा खुलने जैसा होगा। जाहिर है जब तक केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, तब तक तो इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह चिंताजनक है। वामपंथी दलों के नेताओं द्वारा चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल होना यह दर्शाता है कि चीन की भारत विरोधी हरकतों से वे लोग कुछ भी सबक सीखने को तैयार नहीं हैं।

तालिबान ने बढ़ाई चिंता

भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान मसले पर हुई बैठक ने और कुछ किया हो या न किया हो, इसने पूरी दुनिया के सामने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि वहां जल्द हालात को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अफगानिस्तान निकट भविष्य में दुनिया के लिए नया सिरदर्द साबित हो सकता है। भारत को नियमित प्रक्रिया के तहत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाले एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि यह बैठक हुई, जबकि इस महीने के तय कार्यक्रम में इसका जिक्र नहीं था। असल में यह आपात बैठक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के विशेष आग्रह पर बुलाई गई। इसमें जिस तरह की गंभीर चर्चा हुई, उससे साफ है कि व्यापक वैश्विक समाज अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। अमेरिका के अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद वहां उपजे शून्य को तालिबान ने एक अवसर के रूप में लिया है। वह ताकत के बल पर अफगानिस्तान के अधिक से अधिक हिस्से पर कब्जा कर रहा है। इसी वजह से वहां से बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं और शरणार्थियों का एक संकट भी खड़ा हो रहा है।

तालिबान इसलिए ऐसा कर पा रहा है क्योंकि उसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी यह बात पहले स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती आई है। सुरक्षा परिषद की बैठक में भी अफगान प्रतिनिधि ने कहा कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान में प्रवेश के लिए डुरंड रेखा के पास इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान में तालिबान के लिए फंड जुटाने की खातिर इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहां के अस्पतालों में घायल तालिबानों का इलाज भी हो रहा है। ऐसे न जाने कितने सबूत हैं कि पाकिस्तान के इस इनकार का कोई मतलब नहीं रह जाता।

बैठक में अमेरिका का यह साफ करना भी महत्वपूर्ण है कि तालिबान को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की बात सुननी ही होगी और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान पर उसके सैन्य कब्जे को या तालिबान के इस्लामी अमीरात की वापसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैसे अफगानिस्तान के सवाल पर रूस की अगुआई में एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को ही होनी है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के भी शामिल होने की संभावना है। देखना होगा कि सुरक्षा परिषद की बैठक में जो बातें हुईं, उसका इस मीटिंग में क्या असर होता है। यह बात भी समझनी होगी कि अफगानिस्तान के सभी पक्षों के बीच बातचीत का मकसद राजनीतिक सुलह पर सहमति है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को इसके लिए पूरा जोर लगाना चाहिए।

महिलाएं कितनी भी शिक्षित क्यों न हों उन्हें पुरुषों के अपेक्षाकृत नौकरी का माना जाता है कम हकदार

ये तमाम बातें किसी भी वैज्ञानिक शोध से आज तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता विज्ञानियों ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में नौ हजार साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। इस खोज ने उन सभी दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया, जो महिलाओं की भूमिका को आदिम काल से ही परिवार और बच्चों की देखभाल तक सीमित कर रहे थे। यह अकाट्य सत्य है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के बतौर श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप महिलाएं भी सामाजिक लिंग रचनाओं को अपने मन मस्तिष्क पर बैठा चुकी हैं, परंतु क्या यह सभ्यता के विकास की अधूरी और अमानवीय परिभाषा नहीं है?

देशकाल की सीमाओं से परे दुनिया भर में आपदा अपने चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न आए, उसके सर्वाधिक दुष्परिणाम आधी आबादी यानी महिलाओं के हिस्से में आते हैं। इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की हालिया रिपोर्ट से होती है। आइएलओ की रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक ओर वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने आर्थिक मंदी के चलते काम से बाहर कर दिया और दूसरी ओर वे जिन्होंने बीते डेढ़ साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण स्वयं रोजगार छोड़ दिए। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं काम से बाहर हो रही थीं तभी पुरुषों के भी रोजगार छीने गए इसलिए सिर्फ महिलाओं की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, परंतु क्या वास्तविकता इतनी भर है या इससे इतर कुछ सत्य ऐसे भी हैं, जिनकी चर्चा हम जानबूझकर नहीं करना चाहते?

क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं कितनी भी प्रतिभाशाली और शिक्षित क्यों न हों उन्हें पुरुषों के मुकाबले नौकरी का अपेक्षाकृत कम हकदार माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं की पहली प्राथमिकता समाज द्वारा परिवार की देखभाल निश्चित की गई है। अगर पेशेवर जिम्मेदारियां किसी भी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे अड़चन बनती हैं तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित रूप से अपनी पेशेवर जिंदगी का त्याग करें। समाज महिलाओं के प्रति इससे भी कहीं अधिक निष्ठुरता बरतता है और उन्हें विकल्प के रूप में देखता है।

एक ऐसा विकल्प जिसे आवश्यकता होने पर कार्यबल की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाता है और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो पुनः हाशिये पर धकेल दिया जाता है।

इस तथ्य की तह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध खोलते हैं। 18वीं सदी तक स्त्री को घरेलू दायरों तक सीमित करने वाली वैश्विक सोच यकायक प्रथम विश्व युद्ध के समय तब परिवर्तित हो गई जब सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने के लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली जगह की भरपाई महिलाओं द्वारा करने के लिए मुहिम चलाई गई। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और उनकी विपुल क्षमताओं को याद दिलाया गया। महिलाओं से श्रमबल का हिस्सा बनने के लिए आह्वान किया गया। जिन महिलाओं में मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति के अभाव का उलाहना देकर उन्हें कमजोर और डरपोक कहा जाता रहा था वे महिलाएं उन सारी धारणाओं को गलत सिद्ध करते हुए उन फैक्ट्रियों में काम करने लगीं, जहां खतरनाक विस्फोटक सामग्री बनती थी। यहां काम करते हुए उनकी त्वचा पीली पड़ गई जिससे उन्हें 'कैनरी' उपनाम दिया गया।

परिवहन, अस्पताल और वे तमाम क्षेत्र, जो पुरुषों के एकाधिकार माने जाते थे महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। यहां तक कि छह हजार रूसी महिलाएं 'बटालियन आफ डेथ' का हिस्सा बनीं, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा 'द रेस्टोरेशन आफ प्री-वार प्रैक्टिस एक्ट-1919' ने महिलाओं पर दबाव बनाया कि वे अपने पद छोड़ दें जिससे विश्व युद्ध से लौटे सैनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें और ऐसा हुआ भी। वे महिलाएं जिन्होंने पुरुषों के समकक्ष ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन्हें सिर्फ इसलिए कार्यबल से हटा दिया गया, क्योंकि इस पर पुरुषों का अधिकार माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इतिहास पुनः दोहराया गया। इस दौरान 60 लाख महिलाओं ने तमाम ऐसी भूमिकाएं निभाईं, जिन पर पुरुषों का वर्चस्व था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद सांस्कृतिक रूढ़िवादियों ने उन पर दबाव बनाया कि वे नौकरी छोड़ दें। यहां तक कि जिन महिलाओं ने ऐसा करने की अनिच्छा जाहिर की, उनको 'फूहड़' कहा गया।

एक सदी बीत जाने के बाद भी रूढ़िगत मानसिकता की जकड़बंदी आज भी यथावत कायम है। इस सोच का केंद्र बिंदु वर्चस्व के उस भाव से है, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत आर्थिक स्वावलंबन है। यह सर्वविदित सत्य है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी आवाज देती है जिसे परिवार, समुदाय और देशव्यापी रूप से सुना जाता है। सत्ता और प्रभाव के इस सुख को पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था किसी भी स्थिति में बनाए रखना चाहती है। पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक बल को न केवल क्षीण करती है, अपितु उन्हें यह विश्वास भी दिलाती है कि तथाकथित रूप से आर्थिक संसाधनों पर पुरुषों का ही एकाधिकार सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है। 1972 में लियोनेल टाइगर और राबिन फाक्स ने अपनी किताब 'द इंपीरियल एनिमल' में जैविक सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि 'लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होता है। स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य लैंगिक जैविक विशेषता है।' दरअसल मानव सभ्यता को जन्मना बताकर यथार्थ को तोड़-मरोड़कर पेश करने की चेष्टा पहली बार नहीं की गई है। 1971 में चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले जैविक रूप से कमजोर होती हैं।

एक सदी बीत जाने के बाद भी रूढ़िगत मानसिकता की जकड़बंदी आज भी यथावत कायम है। इस सोच का केंद्र बिंदु वर्चस्व के उस भाव से है, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत आर्थिक स्वावलंबन है। यह सर्वविदित सत्य है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी आवाज देती है जिसे परिवार, समुदाय और देशव्यापी रूप से सुना जाता है। सत्ता और प्रभाव के इस सुख को पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था किसी भी स्थिति में बनाए रखना चाहती है। पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक बल को न केवल क्षीण करती है, अपितु उन्हें यह विश्वास भी दिलाती है कि तथाकथित रूप से आर्थिक संसाधनों पर पुरुषों का ही एकाधिकार सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है। 1972 में लियोनेल टाइगर और राबिन फाक्स ने अपनी किताब 'द इंपीरियल एनिमल' में जैविक सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि 'लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होता है। स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य लैंगिक जैविक विशेषता है।' दरअसल मानव सभ्यता को जन्मना बताकर यथार्थ को तोड़-मरोड़कर पेश करने की चेष्टा पहली बार नहीं की गई है। 1971 में चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले जैविक रूप से कमजोर होती हैं।

ये तमाम बातें किसी भी वैज्ञानिक शोध से आज तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता विज्ञानियों ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में नौ हजार साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। इस खोज ने उन सभी दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया, जो महिलाओं की भूमिका को आदिम काल से ही परिवार और बच्चों की देखभाल तक सीमित कर रहे थे। यह अकाट्य सत्य है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के बतौर श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप महिलाएं भी सामाजिक लिंग रचनाओं को अपने मन मस्तिष्क पर बैठा चुकी हैं, परंतु क्या यह सभ्यता के विकास की अधूरी और अमानवीय परिभाषा नहीं है?

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, कोरोना व एड्स की को लेकर फैलाई जाए जागरूकता

दरभंगा । कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा रेड रिबन संपोषित दो दिवसीय प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के दरबार हाल में मंगलवार से शुरू हुआ। बुधवार को दूसरे दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें अंगीभूत महाविद्यालयों के कुल 31 नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। चार सत्रों में कार्यक्रम चला। प्रशिक्षण सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति शशिनाथ झा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एवं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम समय अनुकूल है। इसके सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल पदाधिकारी एवं पियर एजुकेटर को प्रशिक्षित कर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोगों को इससे लाभान्वित कराएं। एड्स एवं कोरोना आदि की समुचित जानकारी प्राप्त कर सुदूर देहातों तक इस जागरूकता अभियान को चलाया जाना चाहिए। कुलसचिव डा. शिवा रंजन चतुर्वेदी ने रेड रिबन के कार्यक्रमों से को विभिन्न बीमारियों एवं महामारियों की जानकारी प्राप्त कराकर भारत को सशक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष छात्र कल्याण डा. सुरेश्वर झा ने रक्तदान को महादान बताया। एड्स एवं कोरोना जैसी बीमारियों को दूर करने में वालेंटियर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देश हित में इसका प्रचार-प्रसार लगातार होना चाहिए। तृतीय सत्र में प्रशिक्षक रेड क्रास सोसाइटी दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी ने रक्तदान विषयक विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नोडल आफिसर एवं पियर एजुकेटर को दी। इस अवसर पर वित्तीय सलाहकार कैलाश राम ने अपने सारगर्भित शब्दों से विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक श्री विनोद बैठा भी मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक सह क्रीड़ा पदाधिकारी डा. सत्यवान कुमार ने किया। इनका सहयोग डा. कमलेंद्र चक्रपाणि ,खेल अनुदेशक पवन कुमार सहनी, भू संपदा पदाधिकारी डा अवधेश चौधरी स्वयं सेवक भवेश झा, मनोरंजन, उजाला कुमारी, निशा, राघव कुमार ,रुपेश कुमार तथा अभिषेक झा ने किया। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि बुधवार को 31 महाविद्यालयों के पियर एजुकेटरों का प्रशिक्षण सुबह 11ः00 बजे से विश्वविद्यालय दरबार हाल में होगा।

पानी के बीच कोई प्यासा कैसे रह सकता है, आप भागलपुर आएं... आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा

भागलपुर । भागलपुर जिला बाढ़ से घिर गया है। हर ओर पानी ही पानी है। लोगों की जिंदगी पानी के बीच कट रही है। इस बीच लोग पानी से प्यासे तड़प रहे हैं। पानी के बीच रहकर भी पानी के तड़प लोगों में देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को दोपहर से गंगा के बढ़ रहे जलस्तर में विराम लग गया। जलस्तर स्थिर हो गया है। पूर्वानुमान की बात करें तो जलस्तर घटने के संकेत मिल रहे हैं। बताया गया कि शाम से जलस्तर में कमी आना शुरू हो जाएगा। उधर जल प्रलय में सबौर के बाढ़ पीड़ितों के हाल बेहाल हैं। पानी में रहकर प्यास से छटपटा रहे हैं। जिंदगी के जिल्लत का आलम यह हो गया है की पानी में ही शौचालय करना है और फिर उसी पानी से स्नान और घरेलू उपयोग करना है। हद तो तब हो गई जब गांव में रह रहे बाढ़ पीड़ित को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। चार से पांच फीट पानी में लंबी दूरी तय कर महिलाएं अपने बच्चों और परिवार के पीने का पानी लाने की जद्दोजहद में लगी रहती हैं। जीवन भर एक एक पाई जमा कर आशियाना बनाया गया और उसे खून और पसीने की मेहनत से सजाया गया। उस आशियाने को छोड़कर बाढ़ पीड़ित शिविर में नहीं जाना चाहते। घर के सामान को जोगने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिंदगी दाव पर लगा दिए हैं। फरका, घोषपुर, इंग्लिश, रजंदीपुर, बाबूपुर, संतनगर, बगडेर, मसाढु, शंकरपुर, अठगामा गांव में चार से पांच फीट तक बाढ़ के पानी का बहाव है। घर-घर में बाढ़ ने पूर्णरूपेण पांव पसार दिया है। उसके बावजूद ग्रामीण अपने अपने घरों में ही रहकर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं।सरकारी व्यवस्था की बात करें तो आवागमन के लिए नाव तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। भोजन की बात तो दूर लोगों को शुद्ध पेयजल की भी उपलब्धता नहीं कराई जा सकी है। बच्चे दूध के अभाव में भूख से बिलबिला रहे हैं। नौनिहालों की मां बस बच्चे को बहला रही है। लेकिन क्षुधा की आग के आगे मां का प्रयास भी विफल हो जा रहा है। अर्थात यूं कहें की सबौर में बाढ़ पीड़ित भगवान भरोसे जिंदा हैं। ऐसा नहीं की सरकारी खर्च आपदा के नाम पर नहीं हो रहा है, बल्कि खर्च के बावजूद लाभुकों तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाने के बाद बोलीं कोमालिका, अगला लक्ष्य सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक

रांची । पोलैंड में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद कोमालिका बारी बुधवार को रांची पहुंचीं। जहां खेल के उपनिदेशक विनय कुमार मिश्र और रांची डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कोमालिका ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य आगामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधना है। इसके लिए बेहतर तैयारी करना जरूरी है। जिस पर उनका सारा ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन रहा। अब अगले इवेंट की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाना है। यहां से कोमालिका बारी जमशेदपुर के लिए निकल गईं। कैडेट विश्वकप में स्वर्ण पदक जीतने पर रांची जिला तीरंदाजी संघ ने हर्ष व्यक्त किया है। संघ की अध्यक्ष नेहा महतो ने ने कहा कि कोमालिका ने पोलैंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 21 महिला वर्ग का स्वर्ण अपने नाम कर एक बडी उपलब्धि हासिल की है।

योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, युवाओं को रोजगार के लिए 3 हजार करोड़ की व्यवस्था

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधान मंडल में पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले छह माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया, जो आम बजट का 1.33 प्रतिशत है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नए रिकार्ड बनाए और कई रिकार्ड तोड़े गए हैं।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि जो अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह बजट लाया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान किया गया है। राजधानी में अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशावर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखान और आयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दिया। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घरों में खाने के लाले पड़े हैं। सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं। उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद 11.45 बजे विधान सभा में सदन के स्थगन की अवधि को 12.20 बजे तक बढ़ाने की घोषणा हुई।

यूपी विधानसभा में महंगाई पर चर्चा कराने को लेकर विफरा विपक्ष, कहा- सदन की परंपरा तोड़ रही सरकार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधान मंडल में पेश करेगी। इससे पहले सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को सदन की कार्यवाही को 12.20 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घरों में खाने के लाले पड़े हैं। सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं। उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है। विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 11.45 बजे विधान सभा में सदन के स्थगन की अवधि को 12.20 बजे तक बढ़ाने की घोषणा हुई।

सदन 40 मिनट के लिए स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार विधानसभा की परंपरा को तोड़ रही है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद नियम 56 में चर्चा कराई जाती रही है, लेकिन आज सरकार ने नियम 56 को 78वें स्थान पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महंगाई पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार तो सदन ही नहीं चलाना चाहती। नेता विपक्ष ने कहा कि महंगाई इतनी है कि लोगों के भूखों मरने की स्थिति है। इस वक्त सिर्फ जनता की जान लेना सस्ता है। सरकार के मुफ्त राशन वितरण को भी उन्होंने मजाक बताया। इससे पहले कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से भागे नहीं। बसपा विधानमंडल दल नेता शाह आलम गुड्डू ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने हंगामा करके सरकार की मदद की है। सरकार तो चाहती ही नहीं कि जनहित के किसी मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि शांति से मांग करनी चाहिए कि सरकार सदन में चर्चा कराए।

तालिबान की तारीफ करने में फंसे सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, भाजपा नेता ने दर्ज कराया मुकदमा

मुरादाबाद । सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं।इस बार उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को सही ठहराते हुए इसकी तुलता भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कर दी।अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन कर सांसद बर्क फंस गए हैं। सम्भल कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर सपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे पर खुशी जाहिर करने में दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

सम्भल लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने सोमवार को बयान देते हुए तालिबान द्वारा किए गए अफगानिस्तान पर कब्जे को भारत स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दिया था।साथ ही कहा था कि तालिबान ने अमेरिका के भी पैर नहीं जमने दिए थे। जबकि दो लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर तालिबान द्वारा किए कब्जे पर खुशी मनाई थी। इस मामले में भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने मंगलवार की देर रात एक बजे कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सांसद ने तालिबान द्वारा किए अफगानिस्तान के कब्जे को देश के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा है। साथ ही उन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए हैं।

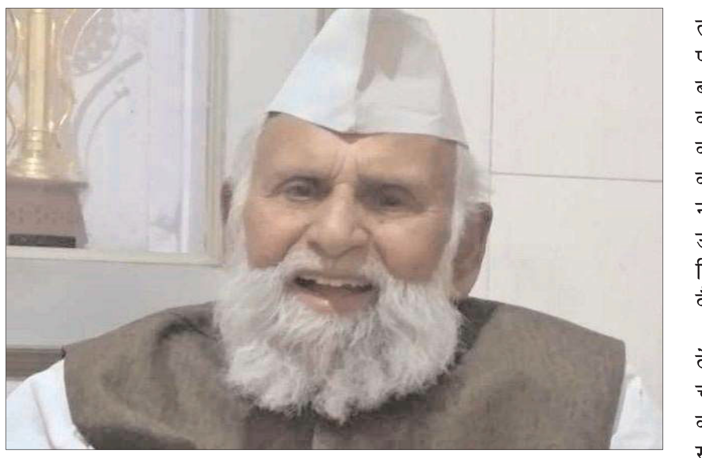

वहीं दो अन्य लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने पर खुशी जाहिर की है। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान, फैजान चौधरी, मोहम्मद मुकीम के खिलाफ धारा 124a, 153a, 195a आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले भी सपा सांसद ने भड़काऊ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना को मस्जिदों, मंदिरों में दुआ करके ही खत्म किया जा सकता है। कोरोना बीमारी भाजपा की गलत नीतियों के चलते आई है। बाद में उन्होंने कोरोना टीके का भी विरोध किया था। हालांकि बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी।

एसपी बोले, इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैंः एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि सम्भल कोतवाली में मंगलवार की देर रात सम्भल कोतवाली में सांसद डॉ शफीकुर्रहमान बर्क व अन्य दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए थे। तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से की थी। तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। यह कार्रवाई राजेश सिंघल की तहरीर पर की गई है।

सांसद बोले, मैंने नहीं दिया ऐसा कोई बयानः उधर, सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क ने ट्वीटर पर पोस्ट करके कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।मैं भारत का नागरिक हूं न कि अफगानिस्तान का, इसलिए वहां क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपने देश की नीतियों का समर्थन करता हूं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज- निद्रा नहीं, चिंतन में लीन थे 'माननीय' कि आक्रोशित जनता का कैसे करें सामना

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज किया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि 'माननीय' सदन में निद्रा में लीन नहीं थे, बल्कि वह इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है, उसका सामना कैसे किया जाए।

दरअसल, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को विधान परिषद कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी। उसी मामले को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये आरोप निराधार है कि 'माननीय' सदन में निद्रा में लीन थे। सच तो ये है कि वो इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है, उसका सामना कैसे

किया जाए और अगले चुनाव में प्रत्याशी कहां से लाये जाएं।

प्रदेश में खत्म हो गया कानून का राज : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। उत्पीड़न, हिंसा और अराजकता से प्रदेशवासी डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदेश की बेटी दुष्कर्म पीड़ित महिला के आत्मदाह की घटना से यूपी शर्मसार है। महोबा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को जिंदा जला दिया गया। ऐसी घटनाएं भाजपा सरकार की विफलता का परिचायक है। अखिलेश ने कहा कि मथुरा में दिनदहाड़े करोड़ों की और गोरखपुर में लाखों की लूट ने एनकाउंटर वाली भाजपा सरकार के समय ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की कलई खोल दी है। ऐसा लग रहा है कि यूपी में अपराधियों ने भाजपा सरकार का ही एनकाउंटर कर दिया है।

असहमति की आवाज दबा रही है भाजपा : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा किमुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में दिनदहाड़े बदमाशों ने आखों में मिर्च पाउडर झोंककर लूट-पाट किया। अखिलेश ने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री कानून का पालन कराने की जगह पुलिस-प्रशासन को ठोको नीति की शिक्षा देते हैं। सरकारी सत्ता के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मकान ढहाए जा रहे है। यह सरकार जेसीबी मानसिकता से कार्य कर रही है। जिसके तहत असहमति की आवाज को दबाया जा रहा हैं। भाजपा ने समाज में राजनैतिक शत्रुता पैदा की है।

मुजफ्फरनगरः विधायक के समर्थन में उतरे गठवाला खाप के चौधरी, बोले- नरेश टिकैत शब्द वापस लें, अन्यथा भाकियू का बहिष्कार

बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। सिसौली प्रकरण में गठवाला खाप के चौधरी बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इस प्रकरण की निंदा करते हुए भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से अपने शब्द वापस लेने को कहा है। चेताया कि यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो भाकियू के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। 10 दिन बाद इस प्रकरण में पंचायत कर निर्णय लिए जाएंगे।

सिसौली में विधायक उमेश मलिक की कार पर पथराव व कालिख फेंके जाने का मामला गरमाता जा रहा है। मंगलवार को गांव खरड़ के किसान इंटर कालेज में गठवाला खाप के चौधरियों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से असामाजिक तत्वों की ओर से विधायक की गाड़ी पर पथराव व कालिख फेंके जाने की निंदा की गई। गठवाला खाप के मुखिया चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि बालियान खाप के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है। चौधरी नरेश टिकैत विधायक को सिसौली में आने से कैसे रोक सकते हैं। उनका बयान बड़बोलेपन को दर्शाता है। जिम्मेदार लोगों को समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए न कि तोड़ने का। जिसने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। चौधरी नरेश टिकैत अपना बयान वापस लें। 10 दिन में बयान वापस नहीं लिया तो भाकियू के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत बुलाकर अहम निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में पंचायत के लिए 50 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। बैठक संचालन गांव खरड़ के पूर्व प्रधान बिजेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान विकास मलिक, विजेंदर सिंह, हरपाल सिंह, जितेंद्र प्रधान, राजवीर सिंह मलिक, कर्ण, ओमवीर सिंह, नितिन पूर्व प्रधान आदि मौजूद रहे।

बयानबाजी को लेकर तनाव, फोर्स तैनात– भाकियू की राजधानी सिसौली में भाजपा विधायक उमेश मलिक पर हमले के बाद दोनों ओर से बयानबाजी का दौर जारी है। तनाव के चलते सिसौली में भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। सीओ स्तर के अधिकारी थाने पर ही कैंप किए हुए हैं। मंगलवार को सिसौली में भाकियू की मासिक पंचायत हुई। इसके अलावा गांव खरड़ में भाजपा विधायक के पक्ष में गठवाला खाप की पंचायत हुई। पंचायत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की। उधर, सिसौली में तनाव के चलते भारी फोर्स तैनात है। मंगलवार को गठवाला खाप और भाकियू की पंचायत के मद्देनजर पुलिस-प्रशासनिक अलर्ट पर रहे। अधिकारी अधीनस्थों से पल-पल की जानकारी लेते रहे।

मंत्री जी बाहर गए हैं– सिसौली में भाकियू की मासिक पंचायत में चौ. नरेश टिकैत के भाषण को लेकर जब केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान से दूरभाषा पर बयान लेने का प्रयास किया तो उनका एक मोबाइल नंबर बंद मिला, जबकि दूसरा किसी अन्य ने उठाया और कहा कि मंत्री जी बाहर गए हुए हैं। वहीं मंत्री के भाई डा. विवेक बालियान ने बताया कि मंत्री जी अस्वस्थ हैं और यहां नहीं हैं।

बिहार में 24 अगस्त से शुरू होगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया, जान लें हर जरूरी बात

पटना। 2021 बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें आखिरकार तय हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक राज्य में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। कुल 11 चरणों में मतदान कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 24 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इससे पहले हम आपको चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों जैसे चरणवार मतदान की तिथि, कुल पदों, प्रत्याशी बनने के लिए अनिवार्य चीजें, नामांकन शुल्क आदि की जानकारी यहां दे रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेगा। 21 वर्ष से कम उम्र वाले किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इसी प्रकार पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। आयोग ने हाल में जारी दिशानिर्देश में कहा है कि नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी को खुद सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने नामांकन पत्र को दाखिल करना होगा। प्रत्याशी को नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करनी होगी।

आयोग के निर्देश के अनुसार पंच व वार्ड सदस्य के पद के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। प्रखंड की किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद की सीटों के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है,

चारा घोटाला को ले नई मुसीबत में लालू यादवः अब पटना में सीबीआइ स्पेशल जज करेंगे सुनवाई, रांची में भी बहस जारी

पटना । राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए यह बुरी खबर है। बिहार में उनके खिलाफ बिहार में दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन मामलों की सुनवाई सीबीआइ के स्पेशल जज करेंगे। स्पेशल जज की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इससे लालू यादव की परेशानियां बढ़ सकतीं हैं। विदित हो कि झारखंड के डोरांडा कोषागार के चारा घोटाला के मामले में भी अब रांची की सीबीआइ कोर्ट में बहस शुरू है। झारखंड में चारा घोटाला के अभी तक के सभी मामलों में सीबीआइ कोर्ट ने लालू को सजा दी है। ऐसे में अगर उनको फिर किसी नए मामले में सजा हो जाती है तो उनका जेल जाना तय है।

पटना हाई कोर्ट ने सीबीआइ के विशेष जज को किया अधिकृत

पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सिविल कोर्ट पटना में लंबित चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज व सीबीआइ के विशेष जज राजेश कुमार को अधिकृत कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जज राजेश कुमार केवल चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। उनके न्यायालय में लंबित अन्य मामले अन्यत्र स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

पटना सिविल कोर्ट में चारा घोटाले के आधा दर्जन मामले लंबित– ज्ञात हो कि पटना सिविल कोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े करीब आधा दर्जन मामले लंबित हैं, जिनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आरोपित हैं। साल 1996 में दर्ज बांका व भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव सहित कई नेता व वरीय अधिकारी आरोपित बनाए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोलीं- अपना दल (एस) और भाजपा मिलकर 2022 करेगी फतह

प्रयागराज । केंद्रीय राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का आज प्रयागराज आगमन हुआ। उन्?होंने कहा कि अपना दल (एस) और भाजपा मिलकर विधान सभा चुनाव 2022 फतह करेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के पुराने सहयोगी दल रहे हैं। 2014 में, 2017 में 2019 में साथ चुनाव लड़े। अब मिशन 2022 भी हम साथ में ही फतह करेंगे। यह गठबंधन जारी रहेगा। दोनों दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चाहिए कि मिलकर कार्य करें। सभी जगहों पर सामंजस्य बनाए रखें।

अनुप्रिया ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश– रायबरेली से केंद्रीय राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को शुरू हुई। प्रयागराज जनपद की सीमा पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। मऊआइमा में केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया ने संक्षिप्त संबोधन में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस मौके पर अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष जमुना प्रसाद सरोज भी मौजूद रहे।

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मऊआइमा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम सरकार के साथ जरूर हैं लेकिन हमारी पार्टी का भी अपना एजेंटा है। हम अब भी उस पर कायम हैं। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में विस्तृत बात हो चुकी है। वह भी हमारे दल की नीतियों व मांगों का समर्थन करते हैं। हमारे एजेंडे में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, जातीय आधार पर जनगणना, अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा का गठन जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये मुद्दे सामाजिक न्याय के हैं। इससे किसी का अहित नहीं होगा। सभी को समान अधिकार और अवसर मिलेगा।

अपना दल (एस) के कार्यकर्ताओं उत्साहित– केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के बाद अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बुधवार को पहली बार प्रयागराज आगमन हुआ। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढ़ाया और उनमें जोश भी भरा।

सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के आरोपित भैरव सिंह ने कहा- सरकार को खुश करने के लिए निगम ने लगाया जुर्माना

रांची । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को रोकने की कोशिश करने के आरोप में सुर्खियों में आए हिन्दुवादी नेता भैरव सिंह ने रांची नगर निगम व जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भैरव सिंह ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रही हैं। सरकार के इशारे पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। रांची नगर निगम द्वारा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाना उसी का हिस्सा है। पिछले दिनों जेल से निकलने पर भैरव के समर्थन में जगह- जगह होर्डिंग लगाए थे। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। अब रांची नगर निगम ने होर्डिंग लगाने के मामले में संज्ञान लेते हुए भैरव सिंह पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भैरव ने कहा कि उसके समर्थकों ने होर्डिंग लगाए। शहर में आए दिन होर्डिंग लगते हैं लेकिन कारवाई सिर्फ मेरे खिलाफ क्यूं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के रवैये को रांची की जनता समझ रही है। लोगों में गुस्सा है। रांची के हरमू किशोरगंज इलाके में जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोकने का प्रयास किया गया। इस मामले में पहले 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 65 नामजद सहित करीब 150 लोगों पर सुखदेवनगर थाने में एफआइआर दर्ज की गई। दरअसल यह पूरा विवाद ओरमांझी में युवती की सिर कटी लाश मिलने के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ। कुछ लोगों का समूह किशोरगंज चौक पर प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान उस रास्ते से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारवां गुजरने वाला था। कुछ लोगों ने काफिले में शामिल वाहनों को रोकने का प्रयास किया। काफिले को एस्कार्ट कर रहे यातायात थाना गोंदा के थानेदार इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने रोड जाम कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान कई लोग उग्र हो गए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मिले गृहमंत्री डॉ. मिश्रा

प्रदेश के गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सौजन्य मुलाकात कर सामयिक चर्चा की।

सीएम आज बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का करेंगे वितरण

श्योपुर और शिवपुरी जिले के बाढ़ पीड़ितों से भी करेंगे बातचीत

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 19 अगस्त को श्योपुर और शिवपुरी जिले के बाढ़ पीड़ित नागरिकों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हुई क्षति के पश्चात अब तक दी गई राहत के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वे इस अवसर पर बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों के बचाव और राहत के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्काल आवश्यक कदम उठाए थे। संबंधित विभागों को सक्रिय किया गया। गत दो सप्ताह में प्रभावित जिलों में जन-जीवन को सामान्य बनाने पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान श्योपुर जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहा, वहां अधोसंरचना को हुए नुकसान का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री शासकीय भवनों सहित निजी मकानों को हुई क्षति की जानकारी भी प्राप्त करेंगे और किसान प्रतिनिधियों से भेंट और फसलों को हुए नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्योपुर में इस माह के प्रथम सप्ताह में आई बाढ़ के फलस्वरूप लोक संपत्तियों की भी काफी हानि हुई है। शासन के प्रयासों से जनहानि को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। बाढ़ में फंसे लोगों को आपदा दलों और सेना ने ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाया। अविलंब चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण अनमोल जिंदगियां बचाने में सफलता मिली।

प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक संगठनों के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भरपूर प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर बाढ़ की स्थिति के बाद गठित 12 मंत्रियों के सदस्यता वाले टास्क फोर्स ने प्रतिदिन समीक्षा कर राहत और बचाव कार्यों पर नजर रखी। मंत्रीगण जिलों में कैंप कर कार्यों का जायजा लेते रहे। श्योपुर में इंदौर और ग्वालियर नगर निगम से कई उपकरण के साथ सफाई कर्मियों के दल बाढ़ के पश्चात तत्काल पहुंचे थे। शहरी क्षेत्र में सड़कों और मार्गों से मलबा हटाने के साथ ही अन्य मार्गों को आवागमन योग्य बनाने पर प्राथमिकता से ध्यान दिया गया। विच्छेद विद्युत लाइनों को पुनः जोड़ा गया।

केंद्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति से प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को भी अवगत करवाया था। हाल ही में केंद्रीय अध्ययन दल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। मंगलवार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी अध्ययन दल के सदस्यों के भोपाल आगमन पर उनके द्वारा किए गए प्रदेश के दो दिवसीय भ्रमण की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुछ योजनाओं और राहत कार्यक्रमों में नियमों से जुड़े ऐसे संशोधन की पहल भी की है, जिससे बाढ़ प्रभावितों को अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जा सके।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम हाउस पर की टीकाकरण कार्य की समीक्षा

प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को चलेगा वैक्सीनेशन महाअभियान

जन-जन तक पहुंचाएं टीकाकरण के महत्व का संदेश

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में दो दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान का द्वितीय चरण 25 एवं 26 अगस्त को चलाया जाएगा। महाअभियान प्रदेश के सभी जिलों में संचालित होगा। इसके लिए अभियान को तीव्र किया जाएगा।श्री चौहान ने बुधवार शाम सीएम हाउस पर वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि वृहद जन-जागृति के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया के माध्यम से टीकों के लाभ, द्वितीय डोज़ की अनिवार्यता एवं उपयोगिता का संदेश प्रचार-प्रसार विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संगठनों आदि संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर वातावरण निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन तक टीकाकरण के महत्व की बात पहुंचाई जाए। दूसरी लहर के नियंत्रित होने के पश्चात आमजन में कोरोना से बचाव की सावधानी में कमी आई है। वैक्सीनेशन के प्रति भी उदासीनता का भाव देखा जा रहा है। जागरूकता के स्तर पर कोई कमी नहीं होना चाहिए। प्रथम डोज़ लगवाने के बाद द्वितीय डोज़ लगवाना बहुत आवश्यक है। अभियान के माध्यम से आमजन तक यह संदेश पहुंचाया जाए। साथ ही दो दिवसीय टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संपादित किया जाए।

टीकाकरण एक नजर में

अब तक वैक्सीन लगाई गई
03 करोड़ 90 लाख 58 हजार 215
18 अगस्त को लगाए गए टीके
05 लाख 68 हजार 414 लोगों को

महाअभियान की सफलता के किए जाएंगे पूरे प्रयास: सारंग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक गांव एवं वार्ड में महाअभियान की सफलता के लिए जोरदार प्रयास किए जाएंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि समस्त कलेक्टर 21 जून को पूर्व में आयोजित महाअभियान के अनुभवों एवं नवाचारों का उपयोग करते हुए कोविड-19 वैक्सीन के प्राप्त सभी डोज़ का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए अभियान पूर्व समस्त तैयारियां समय-सीमा में पूरी करेंगे।

द्वितीय डोज से छूटे लोगों को एसएमएस से भेजे जाएंगे संदेश

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी कि अभियान को सार्थक एप एवं अन्य तकनीक का उपयोग करते हुए द्वितीय डोज़ से छूटे हुए व्यक्तियों को एसएमएस, टेलीफोन, ऑडियो मैसेज के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाएंगे। यह कार्य एक लाख कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 32 हजार से अधिक साथियो एवं पौने चार लाख ब्रिगेड मेम्बर के मोबालाइजेशन द्वारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अब 29 ईको पर्यटन स्थलों का निजी संस्थानों द्वारा किया जाएगा संचालन

वनवासियों को मिलेगा अतिरिक्त रोजगार

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के आरक्षित वनों में ईको पर्यटन की संभावनाओं वाले वन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें मनोरंजन और वन्य-प्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में विकसित कराया जा रहा है। इस तरह के 29 ईको पर्यटन स्थलों पर ईको पर्यटन गतिविधियों के संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव के मकसद से निजी व्यवसायी के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।

ईको पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ सत्यानंद ने बताया कि ईको पर्यटन के लिए 29 स्थलों को संचालन, प्रबंधन और रख रखाव के लिए निजी संस्थानों को 10 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं विकसित कराई जाकर ईको पर्यटन विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। ईको पर्यटन गतिविधियों के संचालन से ऐसे वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले वनवासियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस व्यवस्था के पूर्ण होने पर पर्यटकों को प्रकृति के समीप जाकर उसके विभिन्न घटकों और इन घटकों के बीच परस्पर क्रियाओं को समझने का अवसर भी मिलेगा।

ईको पर्यटन के गंतव्य स्थल

ईको पर्यटन के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास स्थित पनपथा और पेंच टाईगर रिजर्व के पास स्थित दुधिया तालाब और बाइसन हाइवे रिट्रीट की सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद एजेंसी का चयन किया जा चुका है। शेष स्थलों की निविदा जारी करने की शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इनमें भोपाल वन मंडल में रामगढ़, केरवा, समर्धा, बगोनिया, सीहोर में कठौतिया, डिगम्बर जल प्रपात, अमरगढ़ जल प्रपात, खंडवा में धारि कोटला, बोरिया माल, गुंजारी, दक्षिण सिवनी वन मंडल में अमोंदागढ़, अम्मामाई, शारदा मंदिर पहाड़ी, महादेव गुफा और फरीद बाबा, लामाजोती तालाब, जंगल काटेज हिनौता, रायसेन में तितली पार्क, जिप लाइन खरबई, सतधारा जंगल केम्प, कूनो पालपुर में सेसईपुरा, पश्चिम मंडला में रत्नाई पहाड़, गिदली घुघरा, बोकुर दाहर, डिंडौरी में खुरखरी दादर, बड़वाह चिड़िया भड़क, दक्षिण बालाघाट में गांगुलपारा जलाशय, दक्षिण छिंदवाड़ा में देवगढ़, टीकमगढ़ में नोटघाट, बुरहानपुर और दक्षिण बैतूल वन मंडल के अंतर्गत क्रमशः झांझर डेम और सापना के गंतव्य स्थल शामिल हैं।

विद्युत वितरण कंपनियां 23-24 अगस्त को मनाएंगी सोलर रूफटॉप अमृत महोत्सव

भोपाल, (प्रसं)। भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा 23 एवं 24 अगस्त को सोलर रूफटॉप की जन-जागृति के लिए अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा सोलर रूफटॉफ के लिए उपभोक्ताओं में जन-जागृति के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और शिविर आयोजित किये जाएंगे। महोत्सव में भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/रेसिडेन्सीयल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से 150 से अधिक कैम्प आयोजित किए जाएंगे। भोपाल शहर में लगभग 32 परिसरों में सोलर रूफटॉफ को बढ़ावा देने के लिए कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर 24 अगस्त को आईएएस गेस्ट हाउस, चार इमली में भी जन-जागृति शिविर लगाया जाएगा। सोलर रूफटॉप के लगाने से एक ओर जहाँ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर जो उपभोक्ता अपने परिसर में सोलर रूफटॉप लगवाते हैं उनको बिजली बिलों में भी राहत मिलेगी। सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत मिलता रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

खंडवा लोकसभा उपचुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी भाजपा : शर्मा

स्व. नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा किए गए कार्यों को पार्टी आगे बढ़ाएगी

बुरहानपुर, (एजेंसी)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि निमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान का अहम योगदान है। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को भाजपा आगे बढ़ाएगी।

श्री शर्मा अपने प्रवास के दौरान बुधवार को बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि खंडवा लोकसभा के उपचुनाव में कार्यकर्ता भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और स्वर्गीय नंदकुमार सिंह चौहान द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता तक जाएंगे। संगठन तंत्र की मजबूती, सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर भाजपा खंडवा उपचुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा एक कैडर बेस पार्टी है। भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए सक्रिय नहीं होती, बल्कि 365 दिन सक्रिय रहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक 1070 मंडल है। जिनमें से 1034 मंडलों की कार्यसमिति हो चुकी है। भाजपा का मध्यप्रदेश में बूथ स्तर तक बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब कल्याण के मिशन में जुटे हैं। पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह सौंधिया, प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनीस, जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, विधायक सुमित्रा कास्डेकर उपस्थित थीं। श्री शर्मा ने बुरहानपुर संगठनात्मक प्रवास के दौरान सुबह होटल उत्सव में नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, संयोजक, सह संयोजक एवं पालक, नगर केंद्र, ग्राम केन्द्र प्रभारी, मंडल प्रभारी एवं विधानसभा में निवासरत जिला पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम केंद्र संयोजक निवृत्ति कोली के निवास पर भोजन किया।

भाजपा कर रही किसानों का दमन

मीडिया से रूबरू हुए जीतू पटवारी

भोपाल (एजेंसी)। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें मिलकर मध्यप्रदेश के किसानों पर अत्याचार कर रही हैं। मप्र में एक करोड़ से ज्यादा किसान हैं। इनमें से 65 प्रतिशत से अधिक छोटे काश्तकार हैं। प्रदेश का किसान इस समय मूंग बेचने के लिए परेशान हो रहा है और सोयाबीन का किसान भी बुरी तरह परेशान है। यह बात प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

पटवारी ने प्रदेश में मूंग की बम्पर पैदावार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इसमें भी अड़ंगा डाला और काफी दिनों बाद मूंग खरीदी का टारगेट बढ़ाया। पटवारी ने कहा कि जो हाल मूंग के किसानों का है, उससे बुरा हाल सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसानों का है। मध्यप्रदेश के पास हमेशा से सोयाबीन राज्य का तमगा रहा है, लेकिन इस बार मप्र सरकार ने किसानों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने बहुत कम बीज उपलब्ध कराए। उसके बाद सरकार ने कम उपज के बीजों को मान्यता दी। जब किसानों ने खराब बीज की समस्या उठाई तो सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों को सोयाबीन बोना ही नहीं चाहिए। पटवारी ने कहा कि पिछले साल 70 फीसदी सोयाबीन खराब हो गया था, तब सीएम ने कहा था कि वह एक एक अन्न के दाने का मुआवजा और बीमा क्लेम किसानों को दिलाएंगे, लेकिन आज तक वह लिस्ट जारी नहीं हुई।

कमलनाथ सरकार की योजनाओं को पलटा

पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार जय किसान ऋण माफी योजना लेकर आई थी जिसकी पहली दो किस्त में ही प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था, लेकिन शिवराज सरकार बनते ही बिना किसी घोषणा के किसान कर्ज माफी योजना बंद कर दी गई। मैंने पिछले चार विधानसभा सत्र में सरकार से सवाल पूछा कि कितने किसानों की कर्ज माफी शिवराज सरकार कर रही है, हर बार उसका यही जवाब मिला कि इस बारे में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।

जनता आशीर्वाद नहीं, श्राप देगी

प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा को लेकर पटवारी ने कहा, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मध्यप्रदेश की जनता बाढ़ की आपदा से घिरी हुई है, जब बेरोजगारी, महंगाई और महामारी की मार से प्रदेश की जनता उबर नहीं पाई है, तब भाजपा नेता किस से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता इन्हें आशीर्वाद नहीं दे रही है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए श्राप दे रही है।

कांग्रेस ने तीन सदस्यीय जांच कमेटियों का किया गठन

मामला छतरपुर और टीकमगढ़ में अजा वर्ग के साथ हुई घटनाओं का

भोपाल (एजेंसी)। छतरपुर जिले की ग्राम धामची निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के सरपंच हन्नु वंशकार द्वारा ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से नाराज दबंगों द्वारा सरपंच से सार्वजनिक मारपीट कर अपमानित किए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चैधरी ने मप्र कांग्रेस की ओर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया।

गठित जांच कमेटी में किरण अहिरवार, लोकसभा प्रत्याशी 2019 टीकमगढ़ , आरआर बंसल, महामंत्री मप्र कांग्रेस कमेटी, राजू विछोले पूर्व पार्षद नोंगांव छतरपुर को शामिल किया गया तथा टीकमगढ़ के ग्राम श्रीनगर में दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के स्वर्गीय शंकर अहिरवार की हत्या कर फांसी पर लटकाने तथा घटना के गवाहों को धमकाने के मामले में भी तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। गठित जांच कमेटी में पंकज अहिरवार, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस अनु जाति विभाग टीकमगढ़ उषा किशनलाल अहिरवार, प्रदेश संयोजक कांग्रेस अनु जाति विभाग देवीदीन उर्फकल्लन अहिरवार, अध्यक्ष कांग्रेस अनु जाति विभाग छतरपुर को शामिल किया जाकर उक्त दोनों घटनाओं का जांच प्रतिवेदन पांच दिवस में प्रदेश कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

संजय कपूर आज पृथ्वीपुर और कल सतना में लेंगे बैठक

कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे रायशुमारी

भोपाल (एजेंसी)। मप्र में होने वाली तीन विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी संजय कपूर 19 अगस्त को पृथ्वीपुर और 20 अगस्त को सतना में कांग्रेसजनों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री प्रशासन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि श्री कपूर 19 अगस्त को सुबह पांच बजे झांसी पहुंचेंगे और वहां से कार द्वारा ओरछा जाएंगे।

श्री कपूर सुबह 10 बजे ओरछा से निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर जाएंगे और वहां पूर्वान्ह 11 बजे जिला, ब्लाक, मंडलम, सेक्टर अध्यक्ष एवं मोर्चा संगठन के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। वे अपरान्ह तीन बजे सतना के लिए प्रस्थान करेंगे। उनका रात्रि विश्राम सतना रहेगा। श्री कपूर दूसरे दिन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे सतना में जिला कांग्रेस अध्यक्ष, रैगांव विधानसभा के ब्लाक, मंडल, सेक्टर अध्यक्षों एवं मोर्चा संगठन के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। वे रात्रि 8.55 बजे सतना से रवाना होकर 21 अगस्त को सुबह 4.55 बजे भोपाल पहुंचेंगे। वे दोपहर 1.30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्ता से फीडबैक भी लें

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य। बिजली उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत सही बिजली बिल मिलें। उपभोक्ताओं को ऑकलित बिल नहीं दें। जिन घरों में कोई नहीं रह रहा है, वहां बिजली बिल नहीं दें। श्री तोमर ने यह निर्देश पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का विश्लेषण कर यह पता करें कि किस प्रकार की शिकायत अधिक हैं और क्यों हैं। शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लें। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपभोक्ता की तरह सोचें की कम्पनी कैसा कार्य कर रही है। कम्पनी के कार्यों से क्या आप एक उपभोक्ता की हैसियत से खुश हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रबी सीजन में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ट्रांसफार्मर सहित अन्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखें, जिससे कही भी ट्रांसफार्मर या अन्य सामग्री खराब होने पर तुरंत बदली जा सके। इन्सूलेटर सहित अन्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार ही सामग्री क्रय करें। उन्होंने कहा कि वितरण ट्रांसफार्मर में लगे मीटर की रीडिंग नियमित रूप से लें। ट्रिपिंग कम से कम हों। एनर्जी ऑडिट प्रभावी ढंग से करें। श्योपुर एवं शिवपुरी में बाढ़ के दौरान बंद हुई बिजली को पुनः चालू करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाये।

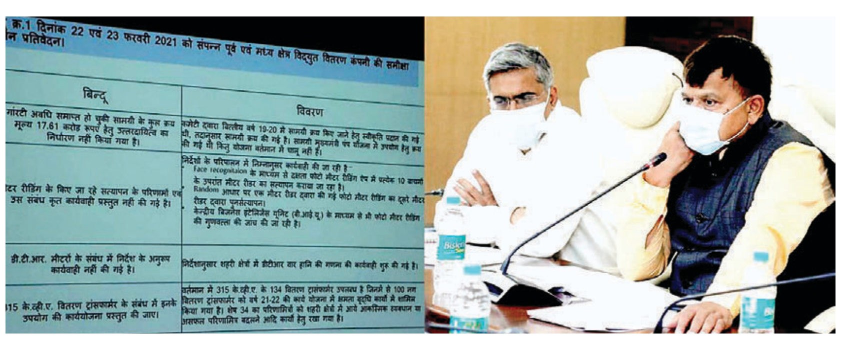

भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा की।

आउटपुट नहीं दिखने पर होगी कार्रवाई

श्री तोमर ने कहा कि किसी भी अधिकारी की सेवाएं कही भी ली जा सकती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि हर हाल में आगामी तीन माह में आउटपुट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का सीआर लिखते समय भी उनकी दक्षता का मूल्यांकन जरूर करें। मेंटिनेंस सुनियोजित कार्य-योजना के अनुसार करें। ट्रांसफार्मर में अर्थिंग ठीक से करें और मेंटिनेंस भी समय-समय पर करते रहें। इससे ट्रांसफार्मर कम खराब होंगे। जिस क्षेत्र में बिजली चोरी ज्यादा होती है, वहाँ प्राथमिकता से केबल लगाएं।

हानियां रोकने जरूरी कदम उठाएं : प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कहा कि जहां पर ज्यादा हानियां हो रही हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर हानियां रोकने जरूरी कदम उठाएं। उन्होंनें कहा कि हर हाल में हानियां कम करना है। श्री दुबे ने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित एवं परिणाममूलक काम करने के निर्देश दिये। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एमडी किरण गोपाल और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के एमडी गणेश शंकर मिश्रा ने कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान सचिव ऊर्जा आकाश त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

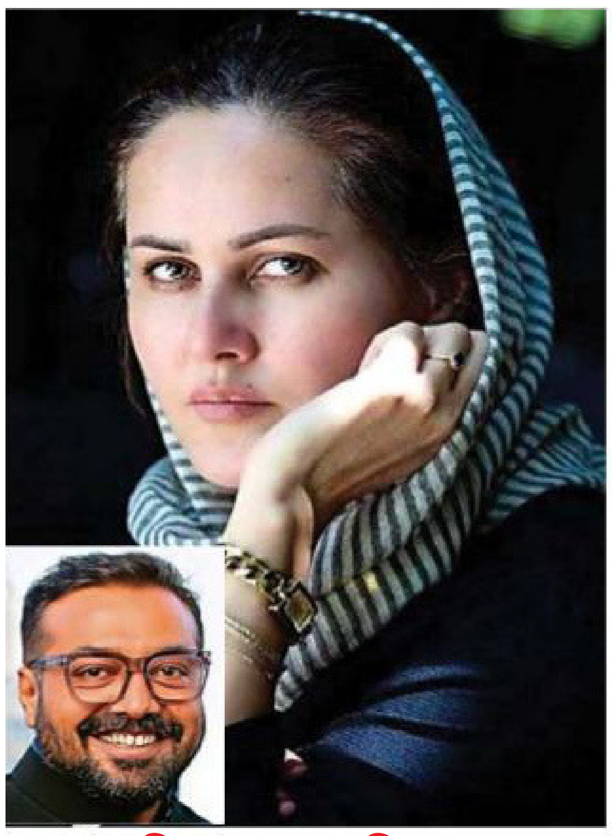

अफगानिस्तान-तालिबान युद्ध

फिल्म निर्देशक सहारा करीमी ने अनुराग कश्यप से मांगी मदद

अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से वहां काफी भयावह स्थिति बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़ने को मजबूर हैं। वहां के ज्यादातर प्रांतों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे संकट के बीच अब अफगान फिल्म निर्देशक सहारा करीमी ने दुनियाभर के फिल्म समुदायों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। सहारा करीमी के पत्र को बॉलीवुड मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इस पत्र में लिखा गया है, 'मेरा नाम सहारा करीमी है और मैं एक फिल्म निर्देशक हूं और अफगान फिल्म की वर्तमान महानिदेशक हूं, जो 1968 में स्थापित एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली फिल्म कंपनी है। मैं टूटे हुए दिल के साथ ये लिख रही हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे खूबसूरत देश को तालिबान से बचाने में शामिल होंगे। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमारे लोगों का नरसंहार किया। कई बच्चों का अपहरण कर लिया गया है। एक महिला को उसके कपड़ों के लिए मार डाला गया। उन्होंने हमारे पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक को प्रताड़ित किया और मौत के घाट उतार डाला। उन्होंने एक प्रागैतिहासिक कवि को मार डाला। सरकार से जुड़े लोगों को मार डाला। कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। लाखों परिवारों को विस्थापित कर दिया। काबुल में परिवार शिविरों में रह रहे हैं। दूध के अभाव में बच्चों की मौत हो रही है। यह एक मानवीय संकट है। लेकिन दुनिया खामोश है। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा– हमें इस चुप्पी की आदत हैं लेकिन हम जानते हैं कि यह सही नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे लोगों को छोड़ने का फैसला गलत है। हमें आपकी आवाज की जरूरत है। अगर तालिबान सत्ता संभालता है तो वह सभी कलाओं पर रोक लगा देंगे। वो महिलाओं के अधिकारों का हनन करेंगे। तब सत्ता पर तालिबान काबिज था तो स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या शून्य थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने कई स्कूलों को तबाह कर दिया है। 20 लाख लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं दुनिया की इस चुप्पी को नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन मैं अपने देश के लिए लड़ूंगी लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकती। मुझे आपके जैसी सहयोगियों की मदद चाहिए। सहारा करीमी ने लिखा, हमें अफगान महिलाओं, बच्चों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं की ओर से आपके समर्थन और आवाज की जरूरत है। आपकी मदद सबसे बड़ी होगी जिसकी हमें अभी जरूरत है। कृपया हमारी मदद करें दुनिया को अफगानों को छोड़ने न दें।

एक भारतीय फिल्म में पाकिस्तानी किरदार निभाना दिलचस्प था : पवन शंकर

अभिनेता पवन शंकर सात साल के विश्राम के बाद फिल्म भुज के साथ पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई प्रमुख मोहम्मद हुसैन उस्मानी की भूमिका निभाई है। पवन का कहना है कि उसका चरित्र एक आदमी के दो चरम पक्षों को दिखाता है, जो अपने देश के लिए लड़ता है और साथ ही एक ऐसी महिला से प्यार करता है जो एक जासूस और दुश्मन है। चूंकि वह एक पाकिस्तानी की भूमिका निभा रहे हैं, भुज जैसी फिल्म में, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के खिलाफ भारतीय सेना की वीरता का जश्न मनाती है, पवन ने कहा कि उन्होंने इसे एक काला चरित्र नहीं बनाने की कोशिश की, लेकिन एक प्रतिपक्षी जो अजय देवगन द्वारा निभाए गए नायक के साथ व्यवहार करता है।

पवन ने बताया, मेरा किरदार उस्मानी एक पाकिस्तानी आईएसआई प्रमुख है, जो भुज के रनवे को नष्ट करने की योजना बना रहा है। मैंने चरित्र में एक सूक्ष्म तत्व बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि भले ही वह एक पाकिस्तानी है, लेकिन वह अपने देश की सेवा करने के लिए कर्तव्य पर है। जब एक आदमी अपने देश को बचा रहा है, वह किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे पता है कि यह गलत हो सकता है और शीर्ष पर जब आप एक भारतीय फिल्म में एक पाकिस्तानी किरदार निभा रहे हैं। लेकिन इसे एक बुरे खलनायक की तरह बनाने के बजाय, चरित्र के साथ लिखे गए थे बहुत सारे मानवीय तत्व। उनके चरित्र में एक भारतीय जासूस हीना रहमान के साथ एक प्रेम कहानी भी है, जिसे नोरा फतेही ने निभाया है। पवन ने साझा किया, वह प्रेम कहानी मेरे चरित्र के दिलचस्प हिस्सों में से एक है जो उसके दिमाग में और अधिक दुविधा लाती है। एक तरफ, वह अपने देश को बचाने के लिए चरम पर जाता है, दूसरी तरफ, वह एक जासूस से प्यार करता है! पवन ने टीवी शो सिद्धांत और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से प्रसिद्धि हासिल की। फिल्म में उनके काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर पवन ने कहा, हमने फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग भोपाल में की। भोपाल में एक ताजमहल है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमने वहां एक प्रमुख हिस्सा शूट किया है। नोरा अपने आप में एक स्टार हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कहना होगा, वह बहुत समर्पित हैं और अधिक काम करने की उसकी तीव्र इच्छा है। वह वास्तव में एक सराहनीय व्यक्तित्व हैं। काश मेरे पास उनके साथ और दृश्य होते। भुज अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित है, जिसमें अजय देवगन, शरद केलकर, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, एमी विर्क और प्रणीता सुभाष प्रमुख हैं। यह सिनेमाघरों में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।

बिग बॉस ने मुझे नई पहचान दीः शहनाज गिल

बिग बॉस 13 की पूर्व प्रतियोगी शहनाज गिल ने कहा कि वह आज जो कुछ भी है इसी विवादास्पद रियलिटी शो की वजह से है। पंजाबी गायिका और अभिनेत्री का कहना है कि इस शो उन्हें एक नई पहचान दिया है। शहनाज, जिन्हें प्यार से पंजाब की कैटरीना कैफ कहा जाता है, का कहना है कि रियलिटी शो ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति भी दिया जिससे वह एक दोस्त(अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला)बता सकती हैं। शहनाज ने कहा, बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया है.एक नई पहचान, भावनात्मक बंधन और एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं एक दोस्त कह सकती हूं। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिग बॉस के ओटीटी घर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्हें और सिद्धार्थ को जो प्यार मिला है, उससे शहनाज अभिभूत हैं। उन्होंने आगे कहा, सिडनाज के प्रशंसकों द्वारा हम पर बरस रहे प्यार और समर्थन को देखना बहुत अच्छा है। मैं फिर से अपने पसंदीदा शो का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं और अन्य जोड़ियों के साथ रहना और करण सर के साथ रहना मजेदार होगा।

अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो यह काम करतीं कियारा आडवाणी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा संग नजर आई है। यह फिल्म कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में कियारा ने कैप्टन विक्रम बत्रा की मंगेतर डिंपल चीमा का किरदार निभाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान देशभक्ति फिल्म में काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि अगर वह एक्ट्रेस नहीं होती तो अभी क्या काम कर रही होतीं। कियारा आडवाणी ने कहा, मैंने शेरशाह की शूटिंग के दौरान जो सीखा, वह मेरा एक अनुभव सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों के प्रियजनों द्वारा किया गया बलिदान था, जिन्हें मैं सलाम करना चाहती हूं। क्योंकि वे गुमनाम नायक हैं, और वे रीढ़ की हड्डी बनाते हैं और एक सेना अधिकारी के लिए ताकत का स्तंभ हैं। मेरे लिए, मेरी सेना और सेना के पीछे की सेना दोनों को मैं सलाम करती हूं। इसके अलावा कियारा ने बताया कि यदि वो एक्ट्रेस ना बनतीं तो बच्चों की मनोचिकित्सक होतीं। कियारा आडवाणी का रुझान शुरू से ही मनोचिकित्सक की तरफ था।

छोटा पर्दा

पवनदीप राजन ने जीता इंडियन आइडल 12 का खिताब

पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता की घोषणा की जा चुकी है। इस रियलिटी शो में पवनदीप राजन विजेता बनकर उभरे हैं। वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं तथा अच्छा गाते भी हैं। वे अन्य प्रतिभाओं के धनी भी हैं। वे कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। 15 अगस्त, रविवार को इस शो का रंगारंग ग्रैंड फिनाले के फिनाले का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। विनर को लेकर फैंस में पहले से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। 6 कंटेस्टेंट्स में से पवनदीप राजन, निहाल टौरो, शनमुख प्रिया, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले और मोहम्मद दानिश में से यह खिताब जीता।

पायल घोष ने अपनी स्पोर्ट्स फिल्म के लिए आमेर कामरा से प्रशिक्षण लिया

अभिनेत्री पायल घोष आगामी बॉलीवुड फिल्म में एक खिलाड़ी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस रोल के लिए मशहूर ट्रेनर आमेर कामरा उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। पायल घोष के नाम पटेल की पंजाबी शादी, फ्रीडम जैसी बॉलीवुड फिल्में और कुछ तमिल फिल्में हैं। एथलीट आमेर द्वारा निर्देशित होने के अपने अनुभव को साझा करते हुए, उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आमेर स्टंट करने में मेरी सबसे अच्छी मदद कर रहा है। मैं अपनी फिल्म के लिए काफी कुछ सीख रही हूं। यह जीवन भर का अनुभव होने वाला है। अपनी आगामी अनटाइटल्ड स्पोर्ट्स फिल्म के बारे में बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म एक बायोपिक नहीं है, यह एक लड़की की कहानी है जो खेल का आनंद लेती है लेकिन उसका परिवार उसे शादी करने और परिवार शुरू करने के लिए मजबूर करता है। फिल्म उसके खेल के लिए प्यार, करियर और उसका परिवार के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में है। आमेर एक वास्तविक जीवन के एथलीट और बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने कई मशहूर हस्तियों को प्रशिक्षित किया है। वह फिल्म के लिए पायल का मार्गदर्शन करने के बारे में विस्तार से बताते हैं कि पायल स्क्रीन पर राज करने जा रही है क्योंकि वह ऊर्जा से भरपूर है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ करती है। वह वास्तव में एक वास्तविक जीवन की एथलीट हो सकती है। लोग उसे लंबी छलांग लगाते हुए, डंडे पर चढ़ते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर दर्शकों को एक अलग पायल देखने को मिलेगी। पायल की अपकमिंग फिल्म रेड है, जो एक रोमांटिक थ्रिलर है।

लौंग लाची जैसा दूसरा गाना नहीं हो सकता-मन्नत नूर

गायिका मन्नत नूर, जो अपने लोकप्रिय गीत लौंग लाची के लिए जानी जाती हैं, मेरा माही नामक एक नए साउंडट्रैक के साथ वापस आ गई हैं। मेरा माही में मन्नत के साथ हंस राज हंस के बेटे युवराज हंस हैं। गायिका ने सोनू के टीटू की स्वीटी, इंदु की जवानी और कई अन्य पंजाबी फिल्मों के गानों के लिए अपनी आवाज दी है। अपने नए गाने के बारे में बात करते हुए मन्नत ने बताया कि मेरा माही एक ऐसा गाना है जिससे हर लड़की जुड़ी होगी। संगीत, वीडियो और बोल अद्भुत हैं। गाने की थीम एक लड़की के बारे में है जो अपने माता–पिता के साथ उस लड़के के बारे में बातचीत कर रही है, जिस तरह के लड़के के साथ वह अपना जीवन बिताना चाहती है। मैंने ट्रैक पर काम करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। जबकि मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, यह विशेष था क्योंकि मुझे इसमें मेरे सह–कलाकार युवराज हंस के साथ भी काम करने का मौका मिला। जैसा कि उन्हें संगीत के शौकीनों से गाने के लिए पहचान मिल रही है, मन्नत ने साझा किया कि गीत की सफलता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है। जब भी आपके काम को प्यार किया जाता है, तो यह आपको पूरी तरह से एक अलग ऊंचाई देता है। लौंग लाची एक असाधारण गीत है और मेरा मानना है कि ऐसा दूसरा गीत नहीं हो सकता है। इसे संगीत प्रेमियों से जिस तरह का प्यार मिला है, वह गर्मजोशी से भरा है। उन्होंने विस्तार से बताया, जब मैंने एक संगीतकार के रूप में अपनी यात्रा शुरू की तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मंच पर प्रदर्शन करते समय मेरे हाथ कांप जाते थे। लेकिन वर्षों से एक्सपोजर और विशेष रूप से लौंग लाची की सफलता ने मेरे आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया है। मुझे ट्रैक की सफलता के बाद कई और ऑफर मिलने लगे। तेजी संधू द्वारा निर्देशित मेरा माही एमएन मेलोडी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर रूट

केएल राहुल 37वें स्थान पर, कोहली पांचवें नंबर पर कायम

दुबई (एजेंसी)। इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में छलांग लगाई है। पूर्व नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज रूट दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 180 रन की पारी की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वह पांचवें नंबर थे, लेकिन दो मैचों में दो शतकों की बदौलत वह 893 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर बैठे कीवी कप्तान केन विलियमसन के करीब आ गए हैं। वह अब विलियमसन से महज आठ रेटिंग अंक पीछे हैं।

आईसीसी के मुताबिक दूसरे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे लोकेश राहुल को भी रैंकिंग में काफी फायदा हुआ है। पहली पारी में 129 रन की पारी की बदौलत वह 19 स्थानों की छलांग के साथ 37वें स्थान पर आ गए हैं। उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग आठ नंबर है, जिस पर वह नवंबर 2017 में रहे थे। पिछले हफ्ते एक स्थान का नुकसान झेलने वाले कोहली पांचवें स्थान पर बने हुए हैं। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी अपना छठा और सातवां स्थान बरकरार रखा है। भारत के खिलाफ श्रृंखला की शुरुआत पांचवें स्थान से करने वाले और पहले टेस्ट के बाद कोहली को पीछे छोड़ने वाले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दो और स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 893 रेटिंग अंक हैं जो शीर्ष पर चल रहे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से सिर्फ आठ कम हैं।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहली और दूसरी पारी में क्रमशः 30 और 55 रन बनाने की बदौलत दो स्थानों के फायदे से आठवें नंबर पर आ गए हैं, जबकि उनके हमवतनों फहीम अशरफ और फवाद आलम ने क्रमशः 48वें और 55वें स्थान पर कब्जा किया है। वेस्टइंडीज की तरफ से जर्मेन ब्लैकवुड दोनों पारियों में 22 और 55 रन बना कर नौ स्थानों के फायदे से 35वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं पहली पारी में तीन रन के चलते शतक से चूके कप्तान क्रैग ब्रेथवेट 18 स्थानों की छलांग से 45वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ऑलराउंडरों में तीसरे स्थान पर खिसके जडेजा

भारत के रविंद्र जडेजा टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में एक स्थान नीचे तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के ही रविचंद्रन अश्विन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के स्टार ऑल राउंडर पहले टेस्ट मैच में गेंद और बल्ले के साथ शानदार ऑल राउंड प्रदर्शन की बदौलत गेंदबाजी रैंकिंग में दो स्थानों के फायदे से नौवें, जबकि बल्लेबाजी रैंकिंग में पांच स्थानों के फायदे से 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

बुमराह एक स्थान के नुकसान से 10वें स्थान पर

गेंदबाजों की सूची में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक स्थान के नुकसान से 10वें स्थान पर हैं जबकि लार्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में चार-चार विकेट चटकाने वाले उनके साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 18 स्थान के फायदे से 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को एक स्थान का फायदा हुआ है। उन्होंने भारत के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट चटकाए थे। तेज गेंदबाज मार्क वुड 37वें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में 30 और 55 रन की पारियां खेलने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम दो स्थान के फायदे से आठवें स्थान पर हैं। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने एक विकेट से जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जर्मेन ब्लैकवुड 22 और 55 रन की पारियां खेलने के बाद नौ स्थान के फायदे से 35वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑलराउंडर जेसन होल्डर पांच स्थान के फायदे से 43वें जबकि कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 18 स्थान के फायदे से 45वें स्थान पर हैं। ब्रेथवेट पहली पारी में तीन रन से शतक से चूक गए थे। होल्डर मैच में चार विकेट चटकाने के बाद दो स्थान के फायदे से शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। वह नौवें स्थान पर हैं। मैच में आठ विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज जेडन सील्स 39 स्थान की लंबी छलांग के साथ 58वें स्थान पर पहुंच गए हैं। केमार रोच भी दो स्थान के फायदे से 11वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चार स्थान आगे बढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दोनों पारियों में चार-चार विकेट चटकाए थे।

कोहली के अंतरराष्ट्रीय करियर के 13 साल पूरे

श्रीलंका के खिलाफ खेला था पहला मैच

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को तेरह साल पूरे किए। 18 अगस्त 2008 को उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की। इस दिन विराट ने भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एकदिवसीय मैच में अपना डेब्यू किया। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

विराट की खासियत है कि उन्होंने दुनिया के हर क्रिकेट मैदान पर रन बरसाए हैं। अपने क्रिकेट करियर में रन मशीन कोहली ने विश्व के खूंखार गेंदबाजों का सामना करते हुए उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 साल पूरे होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मौजूदा समय में कोहली को सबसे अच्छा क्रिकेटर बताते हुए बीसीसीआई ने कहा, 2008 में विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मे पदार्पण किया, 13 साल बाद आज विराट ने 438 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 22937 रन बनाए हैं। साल 2008 में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली को सीनियर टीम में शामिल किया गया। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में वह खास करिश्मा नहीं कर सके। पहले वनडे में वह 12 रन बनाकर आउट हुए। विराट को सफलता साउथ अफ्रीका में साल 2009 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मिली।

विराट कोहली का सभी प्रारूपों में प्रदर्शन

कोहली को मौजूदा समय में क्रिकेट के सभी प्रारूपों का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। किंग कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23 हजार रनों के मुहाने पर खड़े हैं। उन्होंने 94 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 7609 रन बनाए हैं जिनमें उनके 27 शतक शामिल हैं। विराट का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 254 रन नाबाद है। एकदिवसीय क्रिकेट में अगर देखा जाए तो विराट का रिकॉर्ड और भी शानदार है। भारत के लिए 254 वनडे खेल चुके कोहली के नाम 12169 रन दर्ज हैं। वनडे में उनके नाम 43 शतक दर्ज हैं जो मौजूदा समय में क्रिकेट खेले रहे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। वनडे में उनसे ज्यादा शतक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी विराट का जलवा कायम है। उन्होंने क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे ज्यादा 3159 रन बनाए हैं जिनमें उनके 28 अर्धशतक शामिल हैं। टी-20 इंटरनेशनल में विराट का सर्वोच्च स्कोर 94 रन नाबाद रहा है।

टोक्यो पहुंचा भारतीय दल का पहला जत्था

24 अगस्त से होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन

टोक्यो । पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का पहला जत्था बुधवार को टोक्यो पहुंच गया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से होगा।

दरअसल, भारतीय दल का पहला जत्था बुधवार सुबह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टोक्यो के लिए रवाना हुआ था। पैरालंपिक में भारत अपने अभियान की शुरुआत 27 अगस्त से करेगा। इस दिन भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाज अपने-अपने इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। टोक्यो रवाना होने से पहले भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद ने कहा, मैं पदक जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ बाधाएं थीं लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। मैंने उन्हें पार कर लिया। आज मैं देश के लिए खेलने जा रहा हूं। वहीं,

भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के अध्यक्ष दीपा मलिक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम बहुत अच्छी स्थिति में है। बता दें कि पैरालंपिक में 4000 से अधिक खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 24 अगस्त से पांच सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत का 54 सदस्यीय दल भाग लेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा दल है। पैरालंपिक खेलों की नौ स्पर्धाओं में भारत हिस्सा लेगा।

पवन-हेमंत की जोड़ी ने जीता रिलायंस ट्रॉफी इंटर प्रेस बैडमिंटन खिताब

एकल में धीरेन देसाई और नीरज बने चैंपियन

भोपाल। पवन जैन और हेमंत की जोड़ी ने 23वीं रिलायंस ट्रॉफी इंटर प्रेस बैडमिंटन प्रतियोगिता का डबल खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रामकृष्ण यदुवंशी और जीतू बागरे की जोड़ी को 21-18, 21-17 से हराया।

सिंगल्स में धीरेन देसाई और नीरज चैंपियन बने। धीरेन और सचिन रावत की जोड़ी ओपन युगल में भी चैंपियन बनी। भोपाल खेल पत्रकार संघ के तत्वावधान में टीटी नगर स्टेडियम के बैडमिंटन हाल में आयोजित इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में बुधवार को फाइनल मुकाबले खेले गए। एकल फाइनल में नीरज ने रामकृष्ण यदुवंशी को 21-18, 21-19 से हराया। ओपन एकल के फाइनल में धीरेन देसाई ने सचिन रावत को 22-20 21-18 से मात दी। इसी तरह ओपन युगल में धीरेन- सचिन की जोड़ी ने नीरज और सचिन की जोड़ी को 21-18, 21-15 से हराया।

जूनियर विश्व कुश्ती में रविंदर ने जीता रजत

नई दिल्ली। भारत के रविंदर को रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 61 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में बुधवार को ईरानी पहलवान रहमान मूसा से 3-9 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस बीच गौरव बालियान ने मंगलवार को 79 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग और दीपक ने 97 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। रविंदर की फाइनल बाउट के अलावा तीन अन्य भारतीय पहलवान कांस्य पदक के लिए उतरे। भारत के यश ने 74 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग, पृथ्वीराज पाटिल ने 92 किग्रा और कुमार अनिरुद्ध ने 125 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीते।

भारतीय मिश्रित रिले टीम ने जीता कांस्य

अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिपः नाइजीरिया को स्वर्ण और पोलैंड को मिला रजत

नई दिल्ली । भारतीय मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले टीम ने यहां बुधवार को अपनी हीट एक में पहला स्थान हासिल करके केन्या के नैरोबी में चल रही अंडर -20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया।

लेकिन भारतीय रिले टीम शाम को हुए फाइनल में तीन मिनट 20.60 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक ही जीत पायी। अब्दुल रज्जाक, प्रिया मोहन, सुमी और कपिल की मौजूदगी वाली भारतीय टीम ने हीट में 3:23.36 सेकेंड के चैंपियनशिप रिकॉर्ड समय के साथ अपनी हीट जीती, जिसे बाद में नाइजीरिया ने दूसरी हीट में बेहतर किया। नाइजीरिया ने स्वर्ण और पोलैंड ने रजत पदक जीता। भारत की सबसे तेज क्वार्टरमाइलर प्रिया अपनी हीट में चौथे स्थान पर रहीं, लेकिन दो सबसे तेज नॉन-ऑटोमैटिक क्वालिफायर के बीच दौड़ समाप्त करने के बाद उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में जगह बनाई। दरअसल तीन हीट में से शीर्ष दो और हारने वालों में दो सबसे तेज धाविकाओं को फाइनल में स्थान दिया गया। प्रिया 53.79 सेकेंड के समय के साथ ओवरऑल चौथी सबसे तेज धाविका रही, जिसकी बदौलत उन्होंने पोडियम (टॉप तीन) की दौड़ में स्थान सुनिश्चित किया। इस तरह चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले टीम के कांस्य से पहले अंडर-20 विश्व चैम्पियनशिप में भारत के लिए सीमा अंतिल (चक्का फेंक में कांस्य, 2002), नवजीत कौर ढिल्लों (चक्का फेंक में कांस्य, 2014), ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा (भालाफेंक में स्वर्ण, 2016), हीमा दास (400 मीटर में स्वर्ण, 2018) ने पदक जीते हैं।

महिलाओं के लिए छह टीमों का आईपीएल शुरू करना चाहिए

नई दिल्ली। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना मानती हैं कि महिलाओं की आईपीएल की शुरूआत छह टीमों से करने के लिए देश के क्रिकेट में काफी गहराई मौजूद है जिससे राष्ट्रीय टीम के लिए बेंच स्ट्रेंथ सुधारने में मदद मिल सकती है। मंधाना ने कहा कि इस ट्वेंटी20 लीग (आईपीएल) के आने के बाद पुरूषों के क्रिकेट में घरेलू खिलाड़ियों के खेल के स्तर में काफी सुधार हुआ है और ऐसा ही महिलाओं के क्रिकेट में भी हो सकता है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा, पुरूष और महिला खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिये एक समान ही राज्य हैं। इसलिये जब पुरूषों का आईपीएल शुरू हुआ तो तब भी इतनी ही संख्या में राज्य थे। लेकिन साल दर साल खिलाड़ियों के खेल का स्तर बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा, आज जो आईपीएल है, यह 10 या 11 साल पहले भी ऐसा ही था। मुझे लगता है कि महिलाओं के क्रिकेट के लिये भी यह समान ही है। हमारे पास क्रिकेट खेलने वाली उतनी ही खिलाड़ी हैं। मंधाना ने कहा, अभी मुझे लगता है कि हम पांच या छह टीमों से अच्छी शुरूआत कर सकते हैं और शायद एक या दो साल में इसे आठ टीमों का कर सकते हैं।

ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने की हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात

चंडीगढ़। ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और कहा कि वह राज्य और देश को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित करना जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। चोपड़ा बीमार होने के कारण 13 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गए सम्मान समारोह का हिस्सा नहीं बन सके थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केवल खेल संबंधित विषय पर ही चर्चा हुई। चोपड़ा ने कहा, मुख्यमंत्री से मिलना काफी अच्छा रहा। मैं आगामी खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा और देश का नाम रोशन करने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगा। खट्टर ने कहा कि इस महीने के शुरू में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा ने सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि अपने गांव, परिवार और हरियाणा का नाम रोशन किया है।

एनसीए प्रमुख पद के लिए आवेदन करने वाले द्रविड़ एक मात्र उम्मीदवार

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के क्रिकेट प्रमुख के पद के लिए पुनः आवेदन किया है जिससे नवंबर में टी20 विश्वकप के बाद उनके सीनियर राष्ट्रीय टीम में मुख्य कोच रवि शास्त्री की जगह लेने से जुड़ी अटकलों पर विराम लगेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने द्रविड़ का दो साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद आवेदन मंगाए थे। नए संविधान के अनुसार अनुबंध में विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है और चयन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाती है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, हां, राहुल ने क्रिकेट प्रमुख के पद के लिए पुनः आवेदन किया है। अब वास्तव में सेंटर आफ एक्सीलेंस बने एनसीए का चेहरा बदलने के लिए उसने जो शानदार काम किया है उसे देखते हुए यह समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है कि वह पद पर बरकरार रह सकता है।

टी20 धुरंधर को मिली इंग्लैंड टीम में जगह, भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से इन दो खिलाड़ियों की छुट्टी

नई दिल्ली। भारत के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट के तीसरे मुकाबले से पहले मेजबान टीम ने दो बदलाव किए हैं। इंग्लैंड की टीम के ओपनर डॉम सिब्ली के साथ जैक क्राउले को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बल्लेबाज डाविड मलान को तीसरे मुकाबले के लिए टीम में जगह दी गई है। भारत ने लार्ड्स में खेले गए दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। तीसरा मैच लीड्स में 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है।

भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए बुधवार को डेविड मलान ने इंग्लैंड की टीम में वापसी की, जबकि तेज गेंदबाज साकिब महमूद को भी टीम से जोड़ा गया है। सलामी बल्लेबाज डोम सिब्ले को हालांकि टीम से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड ने चोटिल तेज गेंदबाज मार्क वुड को 15 सदस्यीय टीम में बरकरार रखा है। टीम को उम्मीद है कि लीड्स में 25 अगस्त से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए वह फिट हो जाएंगे। जैक क्राउले को टीम में जगह नहीं दी गई है। मलान तीन साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। वह पिछला टेस्ट अगस्त 2018 में भारत के खिलाफ एजबेस्टन में खेले थे, जिसमें इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा, मलान टेस्ट प्रारूप में वापसी के हकदार हैं। सभी प्रारूपों में उन्हें काफी अनुभव है और मुझे यकीन है कि अगर मौका मिलता है तो वह अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहले टेस्ट में दायें कंधे में चोट लगने के बाद हमें उम्मीद है कि मार्क वुड फिट हो जाएंगे। हमारी मेडिकल टीम उनके साथ काम कर रही है। जब हम लीड्स जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। वहीं, साकिब महमूद को टेस्ट पदार्पण का इंतजार है। 24 साल के इस तेज गेंदबाज को इंग्लैंड के श्रीलंका और भारत दौरे के दौरान रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया गया था। स्पिनर जैक लीच टांटन लौटेंगे, लेकिन वह मोइन अली के बैकअप के रूप में स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे। इंग्लैंड की टेस्ट टीम रविवार को लीड्स पहुंचेगी।

बायर्न म्युनिख ने जीता जर्मन सुपर कप

लेवांडोवस्की ने दागे दो गोल

डॉर्टमंड । रॉबर्ट लेवांडोवस्की के दो गोल की मदद से बायर्न म्युनिख ने बोरूसिया डॉर्टमंड को 3-1 से हराकर जर्मन सुपर कप फुटबॉल खिताब जीत लिया।

पोलैंड के स्टार खिलाड़ी लेवांडोवस्की ने बुंदेसलीगा के पिछले सत्र में रिकॉर्ड 41 गोल किये थे। उन्होंने 41वें मिनट में पहला और 74वें मिनट में दूसरा गोल किया। थॉमस मुलर ने 49 वें मिनट में बायर्न के लिए गोल किया। सुपर कप से पहले बायर्न म्युनिख और पश्चिम जर्मनी के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। मुलर का 75 वर्ष की उम्र में रविवार को निधन हो गया था। बोरूसिया डॉर्टमंड की तरफ से रीस ने एकमात्र गोल 64 वें में किया।

तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम घोषित

लंदन । भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपने 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है। मेजबानों ने जैक क्रॉली, डोम सिबली और जैक लीच को बाहर का रास्ता दिखाया है, वहीं डेविड मालन और साकिब महमूद को टीम में जगह मिली है।

मलान तीन साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था, वहीं साकिब महमूद को अगर तीसरे टेस्ट में मौका मिलता है तो वह टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। जैक क्रॉली और डोम सिबली को पहले दो टेस्ट मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वह अब क्रमशः केंट और वारविकशायर लौटेंगे। इंग्लैंड ने चोटिल तेज गेंदबाज मार्क वुड को 15 सदस्यीय टीम में बरकरार रखा है। टीम को उम्मीद है कि लीड्स में 25 अगस्त से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए वह फिट हो जाएंगे। **टीमः** जो रूट (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जॉनी बेयरस्टो, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मालन. क्रेग ओवरटन. ओली पोप. ओली रॉबिन्सन. मार्क वड।

इंग्लैंड के कोच की टीम इंडिया को धमकी, हमारे खिलाड़ियों को हाथ लगाया तो जवाब मिलेगा

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर नजर आई गर्मागर्मी अब मैदान के बाहर की जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। दोनों टीमों की ओर से अब एक-दूसरे पर जिस तरह से शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि इस सीरीज ने वाक युद्ध का रूप ले लिया है। एक दिन पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा था कि अगर कोई प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी हमारे किसी एक क्रिकेटर के खिलाफ छींटाकशी करने की कोशिश करता है तो बाकी बचे 10 खिलाड़ी भी विरोधी टीम के खिलाफ ऐसा ही रुख अख्तियार कर लेते हैं। राहुल के इस बयान के बाद अब इंग्लैंड की टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे लड़ाई से डरते नहीं है और अगर भारत उन्हें गिराने की कोशिश करेगा तो वे भी इसका जवाब देंगे। भारत ने ला?ईस में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से हैंडिग्ले में खेला जाएगा। आमतौर पर दो टेस्ट मैचों के बीच के समय का उपयोग टीमें अपनी तैयारी को पुख्ता करने में करती हैं या फिर हल्के-फुल्के मस्ती-मजाक के जरिये अपने को तरोताजा करने के लिए करती हैं।